संख्या-14 /2024/363/उन्नीस-2-2024-1061/85

प्रेषक

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सूचना अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 12 अगस्त, 2024

विषयः- स्वतंत्रता दिवस समारोह-2024 मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह परम्परागत रूप से सादगी के साथ परन्तु आकर्षक ढंग से मनाया जायेगा।

2 - स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024 के सम्बन्ध में आपकी सुविधा के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है, किन्तु यदि आवश्यक समझा जाये तो व्यावहारिक स्तर पर सुविधानुसार यथोचित परिवर्तन किया जा सकता है।

{1} 15 अगस्त, 2024 को प्रातः 08:00 बजे सरकारी तथा गैर-सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाये तथा झण्डा-अभिवादन के साथ ही राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन हो। राष्ट्रीय ध्वज में पुष्पों की पंखुड़िया बांधकर उसे फहराया जाये।

{2} इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, पंथ-निरपेक्षता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया जाये तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के साथ-साथ लोगों की परम्परागत एकता प्रदर्शित करने के लिए मानव-श्रृंखला बनाने पर भी विचार किया जाये।

{3} समस्त शिक्षण संस्थाओं में इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये, जिसमें राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को संक्षेप में स्वतंत्रता-संग्राम का इतिहास बताया जाये तथा देश के लिए शहीद हुए देशभक्तों के जीवन के प्रेरक-प्रसंगों को दोहराया जाये, जिससे उनमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। इसके अतिरिक्त देशप्रेम की भावना जागृत करने वाले नाटक, विचार-गोष्ठी, वाद-विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, निबन्ध-लेखन से सम्बन्धित प्रतियोगिताएं भी यथा-सम्भव आयोजित करायी जायें। शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ ही शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देने वाले कार्यक्रम भी आयोजित किये जायें। शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे।

{4} स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु खेल विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

{5} स्वाधीनता दिवस पर वीरो का वंदन करने के भाव के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शस्त्र सेना, पैरामिलिट्री बल, सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस बल के पुरस्कृत वीरों, शहीदों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों को मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मानित किया जाये।

{6} 15 अगस्त, 2024 को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी कराया जाये।

{7} प्रत्येक जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकार के विकास कार्यों पर आधारित विकास प्रदर्शनी आयोजित करायी जाये।

{8} स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े स्थलों की विशेष साफ-सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित कराते हुए तथा यथासम्भव 15 अगस्त तक नित्य पुलिस बैण्ड से देशभक्ति गीतों का वादन कराया जाये।

3- अपरान्ह् में परम्परागत रूप से किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा का आयोजन किया जाये जिसमें:-

{ 1 } स्वाधीनता की वर्षगांठ पर जन-साधारण को यह स्मरण कराया जाये कि हमारे अनगिनत देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने जीवन भर संघर्ष करके अपना सब कुछ न्यौछावर कर जो राजनैतिक स्वाधीनता हासिल की थी, उसकी रक्षा करते हुए आर्थिक व सामाजिक स्वाधीनता को और सशक्त बनाने का दायित्व विशेष तौर पर नई पीढ़ी पर है। इस अवसर पर जन-साधारण को बताया जाये कि सभी समुदायों के महापुरूषों ने एकता, आपसी सद्भाव, भाई-चारे व इंसानियत पर बल दिया है। इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर उन महानुभावों के कार्यों का भी आदरपूर्वक स्मरण किया जाये, ताकि समाज में मनुष्य और मनुष्यता का महत्व बढ़े।

{2} राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक **'राष्ट्रीय ध्वज'** के महत्व के विषय में जनमानस को बताया जाये।

{3} पंथ-निरपेक्षता की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए लोगों को प्रेरणा दी जाये कि राष्ट्र और समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भावना से होता है, घृणा से नहीं, मेल-जोल से होता है, वैर-भाव से नहीं, एक-दूसरे के धर्म, जाति, विचारों व महापुरूषों का आदर करने से होता है, अनादर से नहीं।

{4} इस समारोह में यदि किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी को बुलाया जाना सम्भव हो, तो उन्हें ससम्मान आमंत्रित किया जाय।

4- 15 अगस्त, 2024 को ब्लाक, तहसील तथा जनपद स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया जाये। श्रेयस्कर होगा कि इन समारोहों का आयोजन उन्हीं स्थानों पर किया जाये, जहां सन् 1947 में स्वाधीनता मिलने पर जन-समुदाय ने आह्लादित एवं रोमांचित होकर यह उत्सव मनाया था।

5- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 एवं 15 अगस्त, 2024 की रात्रि में सरकारी कार्यालय-भवनों तथा अन्य इमारतों एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया जाये।

6 - स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर अधिकाधिक जन-सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी संस्थाओं, समूहों तथा व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाये, जो 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करने की सदिच्छा व्यक्त करते हैं।

7 - विकास संबंधी शासन की प्राथमिकताओं से जन-मानस को अवगत कराते हुए उन्हें अपेक्षित योगदान के लिए प्रेरित किया जाये, साथ ही बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयासों से आम जनता को अवगत कराया जाये।

8 - प्रदेश सरकार **'सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास'** की अवधारणा को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ तथा सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से किसानों, गरीबों, वंचितों, शोषितों एवं उपेक्षित वर्ग के साथ-साथ प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए **साफ नीयत-सही विकास** के संकल्प को साकार कर रही है। प्रदेशवासियों के सहयोग से उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को 01 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है, इस संकल्प को पूरा करने में सभी का सहयोग अपेक्षित है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में किसान, महिला, युवा तथा गरीब हैं। इनके सशक्तीकरण के लिए विभिन्न नीतियां एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जन सहयोग अपेक्षित है।

9- राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों एवं विकासपरक तथा जन कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से स्पष्ट है कि वर्तमान सरकार प्रदेश के आमजन के विकास, उनकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रश्न पर कितनी संवेदनशील है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हित तथा राज्य के समग्र विकास के लिए संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों, जिनका **संलग्न परिशिष्ट** में उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में जनसभाओं में जनसाधारण को अवगत कराया जाये।

10- यह देश सभी धर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक विश्वास, सद्भावना व एकता से ही प्रगति कर सकता है। वर्तमान सरकार **सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण** के संकल्प को मूर्त रूप प्रदान करते हुए अपराध एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में शांति एवं सद्भाव का वातावरण सृजित करने के लिए इस अवसर पर जनमानस की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाये और लोगों को प्रेरित तथा जागरूक भी किया जाये। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करना तथा स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव जगाना है। अतः इस कार्यक्रम का आयोजन जारी दिशा-निर्देश के अनुसार गरिमामय ढंग से किया जाये।

<u>संलग्नक - परिशिष्ट</u>

12-8-24

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या- 14 /2024/363(1)/उन्नीस-2-2024-1061/85 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि/निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रदेश के मा0 उप मुख्यमंत्री/समस्त मा 0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/मा0 राज्य मंत्रीगण के निजी सचिवों को मा0 महानुभावों के सूचनार्थ।
2. समस्त महापौर, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख अधिकारीगण।
7. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारीगण।
10. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-1/सामान्य प्रशासन विभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों तथा राज्य के समग्र विकास के लिये संचालित महत्वपूर्ण योजनायें एवं कार्यक्रमः-

1. जनसमस्या निवारण :-

जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी व्यवस्था की गयी है। मा0 मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर आयोजित **"जनता दर्शन"** में प्रदेश के कोने-कोने से आये पीड़ितों/शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करके उसका प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा इन्टीग्रेटेड ग्रिवान्स रिड्रेसल सिस्टम (आई.जी.आर.एस.) के तहत दिनांक 24 जुलाई, 2024 तक प्राप्त कुल 5,03,96,306 संदर्भों में से 4,99,08,245 मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया गया। तहसीलों में **'सम्पूर्ण समाधान दिवस'** का आयोजन अब प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार तथा **'थाना दिवस'** दूसरे एवं चौथे शनिवार को आयोजित करते हुए प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई है।

2. आस्था को नमन :-

(1) कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को रु 0 1 लाख प्रति श्रद्धालु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।

(2) सिन्धी समाज के सिंधु दर्शन के तीर्थ यात्रियों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से 20 हजार रुपये प्रतिव्यक्ति अनुदान दिये जाने की व्यवस्था।

(3) जनपद गाजियाबाद स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर 04 मई, 2023 को पर्यटन विभाग को हस्तगत।

(4) श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम के विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में 4 से 5 गुना बढ़ोत्तरी।

(5) जनपद वाराणसी में वैदिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना का कार्य प्रथम व द्वितीय चरण का पूर्ण। पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ।

(6) श्रीराम जन्मभूमि मंदिर अयोध्याधाम तक पहुंच मार्ग योजना के अंतर्गत 03 मार्गों के चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण।

(7) 74 धमार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करके संस्तुति सहित लोक निर्माण विभाग को बजट आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित।

3. कानून व्यवस्थाः-

(1) प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक बेहतर बनाने तथा अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जारी।

(2) साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाने की स्थापना। 1530 जनपदीय थानों में साइबर सेल का गठन। हेल्पलाइन नं0 1930 का संचालन एवं हेल्पलाइन की सहायता से वर्ष 2017 से अब तक 171.51 करोड़ रु0 की धनराशि संबंधित बैंकों में फ्रीज़/होल्ड करायी गई।

(3) प्रदेश में लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद तथा प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू।

(4) 112 यू0पी0 परियोजना को और अधिक जनपयोगी बनाने के साथ-साथ इसके संसाधनों में बढ़ोत्तरी कर कई नयी परियोजना जोड़ी गई हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित माहौल देने के लिए लिंक सेवा शुरू करने का निर्णय, वीमेन पावर लाइन 1090, जी0आर0पी0, फायर सर्विस, महिला हेल्प लाइन 181 सेवा का एकीकरण।

(5) महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन कर अब तक 3,47,34,605 व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 1,32,21,844 व्यक्तियों को चेतावनी एवं 30,954 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही।

(6) प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन का गठन।

(7) राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सुरक्षा व्यवस्था प्रोफेशनल तरीके से सुनिश्चित किये जाने हेतु पृथक से **उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स** नामक नये सुरक्षा बल का गठन।

(8) **ई-प्रॉसीक्यूशन प्रणाली** के उपयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(9) प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही में अब तक 204 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 6,837 घायल। 26,579 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिनमें 18,964 इनामी अपराधी हैं। 76,834 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम तथा 921 अपराधियों के विरुद्ध एन0एस0ए0 की कार्यवाही। गैंगेस्टर अधिनियम के अंतर्गत 139 अरब 15 करोड़ 24 लाख रुपये से अधिक लागत मूल्य की चल/अचल अवैध सम्पत्तियों का जब्तीकरण।

(10) प्रदेश स्तर पर चिन्हित 68 माफिया व उनके गैंग के सदस्यों/सहयोगियों में कुल 1,270 के विरुद्ध 754 अभियोग पंजीकृत तथा 601 की गिरफ्तारी, 349 शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही, 18 के विरुद्ध एन0एस0ए0, 727 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट, माफिया एवं अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित रु0 4,037 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त। साथ ही 28 माफिया व 58 सहअपराधी को सघन पैरवी कराकर दण्डित कराया गया।

(11) 01 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2024 तक महिलाओं/नाबालिगों के विरुद्ध हुए अपराधों में 6,792 प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। पॉक्सो अधिनियम के अपराधों में 16 प्रकरणों में मृत्युदण्ड, 429 प्रकरणों में आजीवन कारावास, 1,633 प्रकरणों में 10 वर्ष से अधिक सजा व 2,057 प्रकरणों में 10 वर्ष से कम सजा से दण्डित कराया गया। अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 3,47,653 मामलों में तथा सत्र न्यायालयों में 11,054 मामलों में सजा करायी गई।

(12) प्रदेश में 124 नये थाने, 84 नई चौकियां, 04 जल पुलिस चौकी, 78 महिला पुलिस चौकी परामर्श, 75 विद्युत निरोधक पुलिस थाना, 10 सतर्कता अधिष्ठान थाना, 04 आर्थिक अपराध इकाई थाने, 06 यूपीएसएसएफ की स्थापना, 05 नये सर्किल, 57 साइबर क्राइम थाना व 06 नये नॉरकोटिक्स थाने की स्थापना।

(13) बिजली चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सभी जनपदों में एक-एक विद्युत निरोधक पुलिस थाना स्थापित। मानव तस्करी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु 75 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों में परिवर्तित।

(14) 1 लाख 55 हजार 830 पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती। प्रदेश में 1,518 थानों में कुल 15,130 महिला पुलिस कर्मियों को नियुक्त करते हुए 10,378 महिला बीटों का आवंटन।

(15) मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय "धार्मिक स्थलों पर निर्धारित मानक के अनुसार ध्वनि प्रसारित हो" के अनुपालन में अभियान के अंतर्गत 1,08,037 लाउड स्पीकर हटवाये गये तथा 1,53,417 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानक के अनुसार कम करायी गयी।

(16) यू0पी0-112 द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2022 से जून, 2024 तक त्वरित आपातकालीन सहायता के तहत 1,67,78,024 आपात सहायता इवेंट तैयार कराकर उन्हें आपात सहायता प्रदान की गई।

(17) महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत यू0पी0-112 द्वारा पूरे प्रदेश में 346 महिला पीआरवी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की गई।

(18) प्रदेश की आम जनता से प्रभावी संवाद हेतु c-plan app से 20,28,029 सदस्य जोड़े जा चुके हैं।

(19) 12 जनपदों-लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कन्नौज, अलीगढ़, बरेली, गोण्डा एवं मुरादाबाद में विधि विज्ञान प्रयोगशाला क्रियाशील।

(20) जन जागरूकता अभियान तथा अफवाहों पर नियंत्रण हेतु 5 लाख डिजिटल वॉलन्टियर को चिन्हित करके डिजिटल माध्यम से सक्रिय किया गया।

(21) पुराने जेल मैनुअल के स्थान पर नवीन संशोधित जेल मैनुअल- 2022 का प्रख्यापन।

(22) प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षित किये जाने हेतु कौशल विकास मिशन के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित।

(23) ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के अंतर्गत 10 जुलाई 2023 से अब तक 10,54,314 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन। इस प्रकार इस अभियान के अंतर्गत कुल 11,48,192 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया गया। इसके माध्यम से प्रदेश में हत्या, डकैती, अपहरण, स्नैचिंग, टप्पेबाजी आदि से सम्बन्धित कुल 1,501 अपराधों का खुलासा कर वैधानिक कार्यवाही की गई।

4. किसानों के हितार्थ ऐतिहासिक फैसले:-

(1) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत जून, 2024 तक कुल 17 किस्तों में 2.62 करोड़ से अधिक कृषकों को कुल रु0 74270.84 करोड़ की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की गयी।

(2) प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में माह जून, 2024 तक कुल 2.52 लाख लाभार्थी कृषकों को कार्ड उपलब्ध कराये गये।

(3) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2024 तक कुल 287.71 लाख बीमित कृषकों द्वारा 255.36 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया। वर्ष 2017-18 से जून 2024 तक कुल 54.50 लाख कृषकों को रु0 4588.49 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

(4) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जून 2024 तक 29864 खेत-तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण। प्रदेश में अब तक कुल 4382 एग्री जंक्शन की स्थापना।

(5) सोलर फोटोवोल्टैइक इरीगेशन पम्प की स्थापना के अन्तर्गत सिंचाई हेतु जून 2024 तक कुल 66309 सोलर पम्पों की स्थापना।

(6) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में 470 क्लस्टरों (23500 हे0 क्षेत्रफल) में प्राकृतिक खेती कार्यक्रम संचालित। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करते हुए वर्ष 2023-24 तक कुल 35100 हे0 क्षे0 को जैविक खेती में परिवर्तित किया गया तथा वर्तमान में 141980 हे0 क्षे0 में जैविक खेती कार्यक्रम संचालित।

(7) किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में रबी एवं खरीफ में अब तक 427.76 लाख कुन्तल बीजों का वितरण।

(8) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2023-24 तक कुल रु0 1120149.66 करोड तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह जून, 2024 तक रु0 22865.36 करोड़ का फसली ऋण वितरित। अब तक 381.69 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण।

(9) वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में माह जून , 2024 तक कृषकों को 623.58 लाख मी0टन विभिन्न उर्वरक एवं 124326.33 मी0 टन/किलो लीटर कृषि रक्षा रसायनों का वितरण।

(10) प्रदेश के कृषक उत्पादक संगठनों के गठन, प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु उ0प्र0 कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) नीति-2020 लागू। माह जून, 2024 तक 3263 एफपीओ का गठन।

(11) उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को 1.79 लाख मिलेट्स (श्रीअन्न) मिनीकिट वितरित।

(12) "सहकार से समृद्धि योजना" 01 अप्रैल, 2022 से संचालित। दीर्घकालीन ऋण के तहत वर्ष 2023-24 में रु0 408.53 करोड़ का ऋण वितरित। वर्ष 2024-25 में दिनांक 12 जुलाई, 2024 तक रु0 7817.15 करोड़ का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया।

(13) सहकारी समितियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 37.92 लाख मी0टन उर्वरक तथा 36,282 कुन्तल बीज का वितरण गया। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों द्वारा मोबाइल एटीएम वैन का संचालन। पैक्स समितियों का बहुसेवा केन्द्र के रूप में विकास।

(14) लखनऊ में आयोजित "किसान सम्मान दिवस" के अवसर पर "मुख्यमंत्री उपहार योजना" के तहत 35 हार्स पावर के 95 ट्रैक्टर चयनित कृषकों को वितरित। प्रदेश में 27 नवीन मण्डी स्थलों का कार्य पूर्ण। 85 नग हाटपैठ का कार्य पूर्ण।

(15) मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना में मण्डी परिषद द्वारा 79,796 कृषकों को रु0 134.76 करोड़ का अनुदान। मण्डियों में किसानों हेतु प्री-इराइवल ई-पास। मण्डी व्यापारियों को डिजिटल पेमेन्ट की सुविधा।

(16) लखनऊ एवं सहारनपुर मैंगो पैक हाउस के माध्यम से 104.13 मैट्रिक टन आम प्रोसेस व पैकिंग कर विभिन्न देशों में निर्यात।

5. गन्ना किसानों को सुविधाएं :-

(1) गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(2) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूर्व के पेराई सत्रों के भुगतान सहित अब तक गन्ना किसानों को 2,53,212 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान।

(3) विगत 7 वर्षों में गन्ना उत्पादकता में 11.72 टन प्रति हे0 की वृद्धि हुई। उत्पादकता में वृद्धि से किसानों की आय में औसत रु0 43,364 प्रति हेक्टेयर की वृद्धि। विगत 7 वर्षों में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 7,386 लाख टन गन्ने की रिकॉर्ड पेराई की गई। गत 07 वर्षों में 786.61 लाख टन चीनी का रिकार्ड उत्पादन।

(4) विगत 07 वर्षों में प्रदेश में 36.33 लाख हे0 क्षेत्र में गन्ने के साथ अंतःफसली खेती से कृषकों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई।

(5) स्मार्ट गन्ना किसान प्रोजेक्ट के माध्यम से पर्ची निर्गमन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता। ऑनलाइन पोर्टल 'caneup.in' एवं 'e-Ganna' ऐप द्वारा सर्वे, सट्टा, कैलेण्डर, पर्ची एवं भुगतान संबंधी सूचना गन्ना किसानों को उपलब्ध।

(6) बन्द पड़ी चीनी मिल पिपराइच एवं मुण्डेरवा में 5000 टीसीडी क्षमता की नयी चीनी मिल मय 27 मेगावॉट कोजन प्लाण्ट की स्थापना का कार्य पूर्ण कर संचालित। रमाला (बागपत) की पेराई क्षमता 2750 टीसीडी से बढ़ाकर 5000 टीसीडी की गई और 27 मेगावॉट क्षमता के विद्युत संयंत्र की स्थापना का कार्य पूर्ण।

(7) ऑनलाइन खाण्डसारी लाईसेंसिंग नीति जारी। प्रथम बार 285 नई खाण्डसारी इकाइयों हेतु लाईसेंस निर्गत। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1241.25 करोड़ रुपये का पूंजीगत निवेश तथा 41,900 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

(8) ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए प्रदेश के 37 जिलों में 3,208 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन। 60,092 ग्रामीण महिला उद्यमी पंजीकृत। समूहों को अब तक रु0 6453.75 लाख का अनुदान वितरित।

(9) कृषक गन्ने की खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं हेतु विभागीय टोल-फ्री नंबर 1800-121-3203 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। अब तक गन्ना किसानों की 60,43,370 शिकायतें निस्तारित।

6. आबकारी विभाग -

(1) आबकारी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 45570.47 करोड़ रु0 का राजस्व प्राप्त हुआ, जो विगत वर्ष से 10.47 प्रतिशत अधिक है। माह जून, 2024 तक रु0 11783.76 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

(2) शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। शीरा वर्ष 2023-24 में जून, 2024 तक कुल 492.87 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ।

(3) प्रदेश में अल्कोहल उत्पादन हेतु 88 आसवनियां स्थापित हैं, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 366.73 करोड़ लीटर है।

(4) भारत सरकार के एथेनॉल ब्लैण्डिंग प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में 68 आसवनियों द्वारा एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है, जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 304.63 करोड़ लीटर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 180.31 करोड़ लीटर तथा इस वर्ष माह जून, 2024 तक 42.25 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ। देश में एथेनॉल की आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है।

(5) यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में कुल 123 प्रस्ताव रु0 36431.36 करोड़ के प्राप्त हुए। जिनमें 110 आसवनियों की स्थापना, 05 वाइनरी तथा 07 यवासवनी की स्थापना के प्रस्ताव शामिल हैं।

7. <u>खाद्य एवं रसद विभाग -</u>

(1) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.83 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेन्डर वितरित। 02 निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल वितरण के तहत प्रथम व द्वितीय चरण में अब तक 151.97 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेन्डर का वितरण।

(2) मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रबी विपणन वर्ष 2024-25 में 2275 रुपये प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए खरीद की गई।

(3) मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान खरीद वर्ष 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी हेतु रु0 2183 तथा ग्रेड-ए हेतु रु0 2203 प्रति कुन्तल मूल्य निर्धारित किया गया। 8,01,730 कृषकों से 53.80 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया।

(4) वर्ष 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों के उत्पादन, उपयोग के निर्देश के क्रम में प्रदेश सरकार ने बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 2500 प्रति कुन्तल निर्धारित करते हुए अब तक 66,903 किसानों से 3.55 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की गई।

(5) प्रदेश के 29 मक्का खरीद वाले जनपदों में 908 किसानो से 4,450.66 मीट्रिक टन मक्का खरीद की गयी तथा कृषकों को 9.30 करोड़ रूपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया गया। प्रदेश के 22 ज्वार खरीद वाले जिलों में अब तक 2787 किसानों से 13340.30 मी0 टन ज्वार क्रय कर रु0 42.37 करोड़ का भुगतान किया गया।

(6) प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त उचित दर दुकानों में ई-पॉस के माध्यम से लाभार्थियों को आधार प्रमाणीकरण और ओ0टी0पी0 प्रमाणीकरण द्वारा खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।

(7) 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के अंतर्गत अब तक अन्य राज्यों के 49,635 राशन कार्डधारकों को उ0प्र0 से तथा उ0प्र0 के 54,64,254 कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया।

(8) एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2024 से 05 वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

8. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण :-

(1) प्रदेश के कृषि सेक्टर के विकास में लगभग 25 प्रतिशत औद्यानिक फसलों का योगदान। प्रदेश के किसानो को उच्च गुणवत्ता के फल एवं सब्जी के पौधों की उपलब्धता तथा नवीन तकनीकी हस्तांतरण के उद्देश्य से इजराइल सरकार के तकनीकी सहयोग से जनपद कौशाम्बी में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स तथा चन्दौली में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल की स्थापना का निर्णय। जनपद सहारनपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स एण्ड वेजिटेबल तथा जनपद लखनऊ में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्नामेन्टल प्लाण्ट्स निर्माणाधीन। 14 मिनी सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस का कार्य पूर्ण, 09 निर्माणाधीन।

(2) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति। गैर-कृषि उपयोग घोषणा के लिए सर्किल रेट पर मूल्य का 2 प्रतिशत शुल्क के रूप में जमा करने से छूट।

(3) पूंजीगत सब्सिडी के अंतर्गत राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम सीमा रु0 5 करोड़ तक प्रदान की जायेगी। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण उन्नयन के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय के 35 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी, (अधिकतम सीमा रु0 1 करोड़ तक) प्रदान की जायेगी।

(4) ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई की अधिक ग्राह्यता हेतु प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत तथा स्प्रिंकलर के लिए लघु सीमान्त कृषकों को 75 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 65 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में लक्षित 1.25 लाख हे0क्षे0 के सापेक्ष 61,561 हे0क्षे0 में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम की सुविधा का कार्य पूर्ण। वर्ष 2024-25 में अद्यतन 23200 हे0क्षे0 में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य पूर्ण।

(5) एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा अन्य कार्यक्रमों में नवीन फलोद्यान, पुष्प, शाकभाजी एवं मसाला एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सम्पादित। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 33,152 हे0 क्षेत्र का विस्तार।

(6) आलू के उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन एवं तकनीक उपलब्ध कराने हेतु जनपद हापुड़ एवं कुशीनगर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है।

(7) 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत "प्रधानमंत्री सूक्ष्म, खाद्य उद्योग उन्नयन योजना" के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 12,593 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के उन्नयन का लक्ष्य, जिसके सापेक्ष 6,672 की पूर्ति। वर्ष 2024-25 में 21,000 लक्ष्य के सापेक्ष 1199 की पूर्ति।

9. उद्योगः-

(1) मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 12 सितम्बर, 2023 को हुई मा0 मंत्रि परिषद की बैठक में ''बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण'' के गठन की अधिसूचना हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। जनपद झांसी के 33 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) का गठन।

(2) प्रदेश में 47 वर्षों के बाद एक नये शहर की स्थापना का सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से बुन्देलखण्ड के बहुआयामी विकास को तेज गति मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत झांसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा की तर्ज पर एक नई इण्डस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य होने के साथ-साथ भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। देश की जीडीपी में प्रदेश का 9.2 प्रतिशत का योगदान है। मा0 मुख्यमंत्री जी ने उ0प्र0 को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है।

(4) दिनांक 10-12 फरवरी, 2023 तक लखनऊ में आयोजित तीन दिवसीय यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कुल 28,029 एमओयू हस्ताक्षरित करते हुए लगभग रु0 36.25 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत 1.06 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा।

(5) इस समिट में 10 हजार से अधिक प्रतिनिधियों का आगमन हुआ। नीदरलैण्ड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यू0ए0ई0, युनाइटेड किंगडम और मारीशस जैसे देशों ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पार्टनरशिप की।

(6) विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश की उल्लेखनीय प्रगति। प्रदेश में विकसित हुई वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को अपना माल भारत व विदेशों के बाजार में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों की निर्बाध रूप से सुविधा होगी।

(7) मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों की सहायता तथा प्रदेश में निवेश आकर्षण को सुदृढ़ करने और राज्य के सर्वसमावेशी विकास के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।

(8) समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा निवेशकों को समुचित सहायता प्रदान करने के लिए ''इन्वेस्ट यूपी'' द्वारा एक ऑनलाइन निवेशक संबंध प्रबंधन पोर्टल 'निवेश सारथी' विकसित किया गया है। निवेश मित्र के अधीन एक केन्द्रीकृत ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली को विभिन्न नीतियों में अनुमन्य प्रोत्साहन के प्राप्त करने की प्रक्रिया स्वीकृत एवं संवितरण हेतु विकसित किया गया है।

(9) उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए एक समर्पित नीति- ''फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई), फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु

प्रोत्साहन नीति-2023 घोषित।

(10) ईज आफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक 'निवेश मित्र' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके माध्यम से उद्यमियों को 43 विभागों की 487 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। उद्यमियों से लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की 97 प्रतिशत से अधिक निस्तारण दर के साथ 'निवेश मित्र' देश में वर्तमान में कार्यरत सबसे कुशल सिंगल विन्डो पोर्टलों में से एक बन गया है। इसके माध्यम से अब तक 12.5 लाख से अधिक स्वीकृतियां डिजिटल रूप से जारी की गई हैं।

(11) उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए उ0प्र0 दुकान और वाणिज्य अधिनियम 1962 के अंतर्गत पंजीकरण पर्याप्त है तथा ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

(12) वर्ष 2022 के उपरान्त व्यापार सुधार कार्ययोजना के भाग के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि सुधार, श्रम पंजीकरण, पर्यावरण नियम, सिंगल विन्डो सिस्टम, उपयोगिता सुधार, निर्माण परमिट जैसे 12 सुधार क्षेत्रों में 352 प्रमुख सुधारों को कार्यान्वित किया गया है। इनमें से 261 सुधार सरकार से बिजनेस (जी 2 बी) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत 91 (जी 2 सी) सुधार किए गए हैं।

(13) यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैण्डीक्राफ्ट पार्क व लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में इन्टीग्रेटेड टॉउनशिप, बरेली में मेगाफूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क व गारमेन्ट पार्क एवं कई फ्लैटेड फैक्ट्री काम्प्लेक्स आदि विकसित हो रहे हैं। फिल्म सिटी से करोड़ों रुपये के निवेश के साथ-साथ रोजगार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत भूमि के ग्रामों का स्मार्ट विलेज के रूप में विकास हो रहा है । जनपद लखनऊ और हरदोई की सीमा पर 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की कार्यवाही।

(14) प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात नीति 2020-25 प्रख्यापित करते हुए निर्यात प्रोत्साहन सम्यन्धी योजनाओं की ईज ऑफ डूइंग विजनेस अवधारणा के तहत पूर्णतया ऑनलाइन व सरलीकृत किया गया है। 15 सेक्टर्स एपेरल्स इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर एण्ड लेदर प्रोडक्ट्स, हैण्डीक्राफ्ट, कारपेट आदि को चिन्हित करते हुए विशेष निर्यात प्रोत्साहन कार्ययोजना तैयार की गई है।

(15) **एक जनपद-एक उत्पाद** वित पोषण योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में 3,215 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए रुपये 16536.45 लाख मार्जिन मनी वितरित। 57,880 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध। वर्ष 2024-25 में अब तक 398 लाभार्थियों को रु0 2697.34 लाख मार्जिन मनी वितरित। लगभग 9,440 व्यक्तियों को मिला रोजगार।

(16) विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा जयंती की पूर्व संध्या पर लाभार्थियों को टूल किट वितरित किये गये। कौशल विकास एवं टूल किट वितरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 25,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

(17) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं चालू वित्तीय वर्ष

में अब तक कुल 5,763 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए रु0 15279.37 लाख की मार्जिन मनी वितरित तथा 46,104 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(18) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कुल 4,990 लाभार्थियों को रु0 18519.25 लाख मार्जिन मनी वितरित। 39,920 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2024-25 में 877 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए रु0 3845.33 लाख की मार्जिन मनी वितरित। 7,016 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(19) मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 02 इकाइयों को रु0 10 लाख की वित्तीय सहायता। प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 के बजट में नई योजना के रूप में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ किया गया है, जिसके लिए रु0 1000 करोड़ का प्राविधान।

(20) एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एमएसएमई नीति-2022 प्राख्यापित। मा0 मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 03 जनवरी, 2024 को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमियों को 51 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए।

(21) प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश के नियोजित औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र के सहयोग की महती आवश्यकता के दृष्टिगत (पीएलईडीजीई) निजी औद्योगिक आस्थानों के विकास की योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में अब तक कुल 11 प्लेज पार्कों की स्वीकृति जनपद उन्नाव, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, सीतापुर, अलीगढ़, कानपुर देहात, हापुड़, सम्भल, झांसी एवं मथुरा में की जा चुकी है।

(22) ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में एमएसएमई क्षेत्र के 2,605 एमओयू के रु0 39967.99 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को शामिल किया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र हेतु रु0 30,826 करोड़ के मेगा ऋण वितरण समारोह में लाभार्थियों को वितरित किया। मुख्यमंत्री जी ने 27 जून, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर इकाइयों को रु 0 20000 करोड़ के ऋण वितरण का शुभारम्भ एवं रानी लक्ष्मीबाई प्लेज पार्क झांसी का उद्घाटन किया।

(23) उ0प्र0 निर्यात नीति-2020-25 प्रख्यापित। प्रत्येक जिले में निर्यात प्रोत्साहन समिति का गठन। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अद्यतन 3384 निर्यात ईकाइयों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया। वर्ष 2023-24 में 703 इकाइयों के दावों के सापेक्ष रु0 799 लाख का भुगतान किया गया।

10. सूचना प्रौद्योगिकी:-

(1) उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 के अंतर्गत संशोधित नीति में लक्ष्यों को उच्चीकृत करते हुए 08 डाटा सेन्टर पार्कस् तथा प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 900 मेगावॉट क्षमता का पुनरीक्षित लक्ष्य निर्धारित। उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के अंतर्गत कुल रु0 1486.98 करोड़ निवेश तथा 19,360 रोजगार संभावनाओं युक्त 15 परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रस्तावों पर कार्यान्वयन इकाई हेतु 12 निवेशकों को लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत।

(2) लखनऊ में 19 फरवरी, 2024 को आयोजित ग्राउण्ड ब्रेकिंग समारोह में सूचना प्रौद्योगिकी

एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की रु0 90,778.89 करोड़ की कुल 53 परियोजनाओं की ग्राउण्ड ब्रेकिंग सम्पन्न हुई। इन परियोजनाओं में 75,385 लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से निवेशकों से रु0 157 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

(3) स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित। आगामी वर्षों में 2 करोड़ टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित होंगे।

(4) उत्तर प्रदेश की आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस नीति बनाकर प्रख्यापित किये जाने की भावी कार्ययोजना।

(5) उत्तर प्रदेश सेमीकन्डक्टर नीति- 2024 प्रख्यापित। सेमीकन्डक्टर ईकाइयों के लिए डेडीकेटेड प्रावधान प्रारम्भ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बना। नीति के अंतर्गत रु0 40223.38 करोड़ की निवेश परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त , इससे 32,500 से अधिक रोजगार का सृजन होगा।

(6) उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 के अंतर्गत 04 उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना के प्रस्तावों पर मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश में मान्यता प्राप्त 2,544 नये स्टार्टअप कार्यरत हुए। इस अवधि में 130 स्टार्टअप को रु0 8.09 करोड़ के प्रोत्साहन अनुमोदित किये गये। 15 इन्क्यूबेटर्स को रु0 3.25 करोड़ के वित्तीय प्रोत्साहन संवितरित। इस वर्ष 04 स्टार्टअप्स को रु0 28.75 लाख के वित्तीय प्रोत्साहन अनुमोदित।

11. जी0एस0टी0:-

(1) वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,10,346 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करते हुए 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2024-25 में माह जून 2024 तक रु0 28334.11 करोड़ का राजस्व प्राप्त।

(2) जी0एस0टी0 में समाधान योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3.35 लाख व्यापारी लाभान्वित। रेस्टोरेन्ट के व्यापारियों को मात्र 05 प्रतिशत जी0एस0टी0 जमा किये जाने की अलग से समाधान योजना लागू।

(3) उ0प्र0 में जी0एस0टी0 में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश के सभी राज्यों से सर्वाधिक है। प्रदेश में निर्गत जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या 32.74 लाख हो गई।

(4) मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत वर्ष 2017-18 से अब तक 1,258 व्यापारी लाभान्वित।

12. नगर विकास :-

(1) स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत **'इंडिया स्मार्ट सिटी अवॉर्ड कॉंटेस्ट'** में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 अवॉर्ड प्राप्त हुए। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में प्रदेश के दो शहर आगरा व वाराणसी निरन्तर प्रथम 10 शहरो व तीन शहर आगरा, वाराणसी व कानपुर प्रथम 20 शहरों में सम्मिलित रहे।

(2) स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के चयनित 10 शहरों में स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवरेज, पथप्रकाश, स्मार्ट मार्ग व पार्किंग, पार्कों व वाटर बाडीज के स्वीकृत कार्यों में 613 कार्य पूर्ण।

(3) राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत प्रदेश के 07 शहरों अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, मेरठ व शाहजहांपुर में 608.10 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट रोड ,

स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट क्लास, सोलर स्ट्रीट लाइट, हेल्थ एटीएम, सीसीटीवी, इन्टीग्रेशन, सूर्य नमस्कार, सीनियर केयर सेन्टर, जोनल कार्यालय, सोलर स्ट्रीट लाइट आदि कार्य प्रगति पर।

(4) **प्रधानमंत्री आवास योजना** (शहरी) के अंतर्गत तक कुल 17.70 लाख आवास स्वीकृत, जिसमें से 15.20 लाख आवास पूर्ण।

(5) प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 13,38,452 पथ विक्रेताओं को 2561.54 करोड़ रुपये ऋण वितरित। ऋण वितरण में उ0प्र0 का देश में प्रथम स्थान।

(6) **अमृत योजना** के अन्तर्गत प्रदेश में 11312.10 करोड़ रुपये लागत की जलापूर्ति, सीवरेज व कुल 723 परियोजनाओ में से पेयजल की 160, सीवरेज की 93 परियोजनाएं, हरित भूमि व पार्क विकास की 293 परियोजनाएं पूर्ण। साथ ही 8.81 लाख पेयजल गृह संयोजन तथा 8.19 लाख सीवर गृह संयोजन पूर्ण। नगरीय निकायों में 280 एमएलडी क्षमता के 12 एसटीपी एवं 200 एमएलडी क्षमता के 03 डब्ल्यूटीपी का कार्य पूर्ण।

(7) अमृत-2.0 मिशन के तहत 126 नगरीय निकायों में 331.73 करोड़ रुपये लागत की अमृत सरोवरों के पुनर्जीवन हेतु 194 परियोजनाएं स्वीकृत।

(8) स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)-1.0 के अंतर्गत 82 नगरीय निकायों में 133.65 लाख टन एकत्रित लिगेसी वेस्ट में से 82.76 लाख टन लिगेसी वेस्ट का निस्तारण तथा 09 लाख व्यक्तिगत शौचालयों, 69,381 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। प्रदेश के 189 निकायों में महिलाओं के लिए 1100 पिंक शौचालयों का निर्माण। 762 नगरीय निकायों में 933 मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) अधिष्ठापित कराने का कार्य प्रक्रियाधीन, इसमें से 709 मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी संचालित।

(9) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन हेतु समस्त नगरीय निकायों द्वारा आवश्यक उपकरण एवं मशीनों का क्रय। नवसृजित/विस्तारित निकायों में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास हेतु 996 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत।

(10) दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण हेतु स्वीकृत 155 योजनाओं में से 144 पूर्ण। 13 शहरों में 8,886 शहरी पथ विक्रेताओं के लिए स्वीकृत 50 वेण्डिंग जोन निर्माण में से 11 निर्माण कार्य पूर्ण। 5.70 लाख शहरी गरीब परिवारों को गतिशील कर 57,038 स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुए 41,733 समूहों को रु0 41.73 करोड़ रुपये रिवाल्विंग फण्ड के रूप में अवमुक्त किया गया। 92,336 लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर 54,459 लाभार्थियों को सेवायोजित किया गया।

(11) नगरीय निकायों में संचालित सुविधाओं एवं कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए नगरीय निकाय निदेशालय में प्रदेश स्तरीय डीसीसीसी व्यवस्था, जन समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई के लिए तकनीक आधारित 'सम्भव' पोर्टल की व्यवस्था तथा प्रदेशव्यापी टोल फ्री नं0 1533 संचालित। जनसामान्य की सुविधा के लिए सभी नगरीय निकायों में ई-नगर सेवा लागू।

(12) प्रदेश में सीवर एवं सैप्टिक टैंक की सफाई हेतु सफाई मित्रों के सहयोग के लिए इमरजेन्सी रिस्पॉन्स सेनिटेशन यूनिट का गठन। मैनुअल कार्य पद्धति के स्थान पर मशीनरी एवं

आधुनिक तकनीक के सहयोग से संचालित ''वन सिटी-वन ऑपरेटर योजना'' भारत में प्रथम बार प्रदेश में लागू।

(13) प्रदेश के नवसृजित/सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नगर निकायों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना संचालित। विभिन्न निर्माण कार्य प्रगति पर। प्रदेश के शहरी गरीबों के हितार्थ राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना का क्रियान्वयन।

(14) आकांक्षी नगर योजनान्तर्गत कुल 762 नगरीय निकायों में से सबसे पिछड़े 100 नगर निकायों में आधारभूत अवसंरचना के निर्माण एवं विकास हेतु 150 करोड़ रुपये स्वीकृत।

(15) फेम इण्डिया स्कीम-2 के तहत नगरीय परिवहन को सुलभ व सुरक्षित बनाने हेतु 14 शहरों में 700 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी एवं पैनिक बटन की व्यवस्था के साथ व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग हेतु चार्जिंग स्टेशन के निर्माण की प्रक्रिया गतिशील। प्रदेश के 07 शहरों में 500 ई-ऑटो संचालित कराने की कार्यवाही गतिशील। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नगरीय परिवहन की बसों में कॉमन मोबिलिटी कार्ड-'वन यूपी वन कार्ड' की व्यवस्था।

(16) प्रदेश के निराश्रित गोवंशों के संरक्षण हेतु कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु योजना के अंतर्गत 448 निकायों में गो-आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य प्रगतिशील।

(17) वित्तीय वर्ष 2023-24 में 86 निकायों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु रु0 2390.61 लाख की धनराशि अवमुक्त।

(18) मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अरवन) के तहत नगरों में सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए बेहतर सड़क निर्माण हेतु 16 नगर निगमों को 432 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत।

(19) प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 'वंदन' योजना के तहत 137 निकायों हेतु 209.16 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत। योजना के तहत पेयजल, सीवरेज, जल निकासी, सड़क, पथ प्रकाश एवं सौन्दर्यीकरण आदि की व्यवस्था की जाएगी।

13. <u>जलशक्ति :-</u>

(1) प्रदेश सरकार द्वारा कुल 735 अदद सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, जिसमें 44.54 लाख हे0 सिंचन क्षमता का हुआ सृजन। 153.04 लाख कृषक लाभान्वित।

(2) प्रदेश में कुल नहरों की लम्बाई 75090.90 किमी0 है तथा जलाशयों की संख्या 71 है। चलित राजकीय नलकूप 35,336 हैं।

(3) प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा हेतु अब तक कुल 1251 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण करते हुए 28.23 लाख हे0 से अधिक भूमि का बचाव तथा 213.31 लाख से अधिक आबादी के किसानों को लाभान्वित किया गया। मध्य यांत्रिक की 44 अदद परियोजनाएं पूर्ण। इस क्षेत्र की 28,792 हे0 क्षे0 भूमि एवं 24,986 कृषक लाभान्वित हुए।

(4) केन-बेतवा लिंक परियोजना के निर्माण हेतु प्रदेश सरकार ने रु0 5115.29 करोड़ का

किया प्राविधान। इस परियोजना के पूर्ण होने से प्रदेश में 1700 एम0सी0एम0 पानी तथा 1.78 लाख हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध होगी।

(5) मध्य गंगा स्टेज-2 परियोजना प्रक्रियाधीन। परियोजना पूर्ण होने पर जनपद अमरोहा, संभल, मुरादाबाद में कुल 1.46 लाख हे0 सिंचन क्षमता का सृजन होगा एवं 4,10,348 कृषक लाभान्वित होंगे। जनपद महराजगंज में रोहिन नदी पर रोहित बैराज का निर्माण कार्य प्रगति पर। परियोजना पूर्ण होने पर 8,811 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन एवं 16,000 कृषक होंगे लाभान्वित।

(6) तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

(7) जनपद महराजगंज में स्थित छोटी गण्डक नदी को पुनर्जीवित किया गया। नेपाल से जनपद महराजगंज में प्रवेश करने के उपरान्त यह नदी लगभग 10 किमी0 मृतप्राय हो गई थी, जिसको पुनर्जीवित करते हुए 22 ग्रामों की 48,500 आबादी को सुरक्षा तथा 1,950 हे0 कृषि योग्य भूमि को सुरक्षा प्रदान की गई।

14. नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति :-

(1) नमामि गंगे परियोजना राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत 63 सीवर शोधन परियोजनायें लागत रु0 14067.98 करोड़ की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। 650.05 एमएलडी क्षमता के 33 सीवरेज शोधन संयंत्र पूर्ण। 16 परियोजनायें निर्माणाधीन।

(2) 35 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट निर्माणाधीन हैं, जिनकी क्षमता 707.30 एम०एल०डी० है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नालों द्वारा नदियों में प्रवाहित गंदे जल का शोधन कर नदियों में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम करना। 69 घाटों एवं 13 शवदाह गृह का निर्माण। वाराणसी नगर में 26 घाटों तथा 08 कुण्डों का पुनरुद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण।

(3) नदियों के किनारें अब तक राज्य में 8820.15 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 46,39,275 पौधों का रोपण।

(4) प्रयागराज में 07 घाट एवं फतेहपुर में 01 घाट अक्टूबर 2024 तक होंगे पूर्ण। 25 शहरी निकाय रिवर सिटी एलान्यस प्लेटफार्म पर बोर्ड किये गये। कानपुर एवं अयोध्या के अर्बन रिवर मैनेजमेन्ट प्लान तैयार। नदी जल की गुणवत्ता की जाँच हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है। गंगा नदी पर 36 स्थानों से माह मई 2024 में नेशनल वॉटर क्वालटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत लिये गये सैम्पल की जाँच से उत्साहजनक नतीजे प्राप्त।

(5) गंगा नदी के समीप 231 आर्द्रभूमि चिन्हाकित कर मूल्यांकन करते हुए प्रबंधन की कार्यवाही प्रचलित। ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देते हुए गंगा किनारे के 27 जनपदों में 1,23,580 हे0 क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की निर्मलता एवं अविरलता को सुनिश्चित करने हेतु जन-जन को नदियों से जोड़ने के प्रयास में अर्थगंगा की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे हैं प्रयास।

(6) भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक पाइप

पेयजल योजना द्वारा अनाच्छादित बस्तियों को ''हर घर को नल से जल' उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में जल जीवन मिशन ''हर घर जल'' कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 2.2359 करोड़ घरों में एफएचटीसी के माध्यम से पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। अवशेष 42.25 लाख घरों को वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जायेगी।

(7) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 41 सतही स्रोत जल आधारित एवं 423 भूजल आधारित पाइप पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से 3,748 राजस्व ग्रामों में अद्यतन 10 लाख 92 हजार घरों में जलापूर्ति। विंध्य क्षेत्र में 21 सतही स्रोत एवं 140 भूजल आधारित परियोजनाओं के माध्यम से 2,998 राजस्व ग्रामों के 5,27,230 घरों में पेयजल आपूर्ति।

(8) प्रदेश में जल जीवन मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से कुल 1,14,807 स्कूलों एवं 1,51,258 आंगनबाड़ी केन्द्रों को पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति।

(9) भारत सरकार द्वारा संचालित अटल भूजल योजनांतर्गत प्रदेश के 26 विकास खण्डों की 550 ग्राम पंचायतों का चयन करते हुए जनसहभागिता के माध्यम से जल संचयन के विभिन्न कार्य। उ0प्र0 अटल भूजल योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू।

(10) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक 'हर खेत को पानी' एवं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 2,32,795 निःशुल्क बोरिंग/उथले नलकूप, गहरी बोरिंग 3,620 व 7,467 मध्यम बोरिंग नलकूप पूर्ण। 167 तालाब व 176 चेकडैम का निर्माण, 1,955 ब्लास्ट कूप का निर्माण।

15. अवस्थापना सुविधाओं का विकास :-

(1) पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए 340.824 किमी0 लम्बे 06 लेन चौड़े (08 लेन विस्तारणीय) एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण। मा 0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 नवम्बर, 2021 को किया गया लोकार्पण। यातायात संचालित। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(2) बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे-296 किमी0 लम्बे एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण। मा 0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 जुलाई, 2022 को लोकार्पण। एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।

(3) गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण प्रगति पर।

(4) पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से बलिया को जोड़ने हेतु गाजीपुर से बलिया होते हुए माझी घाट तक 114.650 किमी0 बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे बनाये जाने का कार्य प्रगति पर।

(5) मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी0 लम्बे लगभग रु0 36230 करोड़ लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण का कार्य प्रगति पर।

(6) उत्तर प्रदेश में डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए चयनित सभी 06 नोड्स अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि अर्जन करने के उपरान्त विभिन्न उद्यमियों को आवंटित एवं कार्य स्थल का विकास प्रगति पर।

(7) अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्याधाम संचालित। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर सहित प्रदेश में 04 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स क्रियाशील। जनपद गौतमबुद्धनगर में 5000 हे0 में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) उत्तर भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। प्रदेश के आपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या 15 (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, हिंडन, बरेली, कुशीनगर, अयोध्या, आजमगढ़, अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं मुरादाबाद) हो गयी है।

(8) प्रदेश में अप्रैल 2017 में 04 क्रियाशील एयरपोर्ट से 25 डोमेस्टिक और इण्टरनेशनल डेस्टिनेशंस कनेक्टेड थे वहीं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 15 क्रियाशील एयरपोर्ट से 85-89 डोमेस्टिक तथा इण्टरनेशनल डेस्टिनेशंस कनेक्टड हैं।

(9) जेवर में बन रहे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश देश में 05 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा।

16. ऊर्जा :-

(1) प्रदेश में स्थानीय व्यवधान को छोड़कर निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है। माह अप्रैल, 2024 से माह जून, 2024 तक की अवधि में प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गई।

(2) प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 38 नये 33/11केवी विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत एवं 366 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गई।

(3) किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को 48 घण्टे में बदलने की व्यवस्था।

(4) सिंचाई की सुविधा हेतु किसानों के अब तक 1,36,772 निजी नलकूप का संयोजन निर्गत किये गये।

(5) पारेषण तंत्र में विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी व मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 लखनऊ में चयनित 20,067 मजरों में खुले तारों वाली एलटी विद्युत लाइनों को एलटी एरियल बंच केबिल से प्रतिस्थापना का कार्य पूर्ण। वर्ष 2023-24 में 26 नग विद्युत उपकेन्द्रों का ऊर्जीकरण किया गया। इन उप केन्द्रों के ऊर्जीकरण से ग्रिड में 15,039 एमबीए परिवर्तक क्षमता का संयोजन एवं 3,640 सर्किट किमी0 पारेषण लाइनों का ऊर्जीकरण किया गया। वर्ष 2024-25 में 28 नग उप केन्द्रों का ऊर्जीकरण किया जाना लक्षित होगा।

(6) पश्चिमांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा कुल 867 नये कृषि पोषकों का निर्माण किया गया।

(7) स्मार्ट मीटरिंग घटक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि 0 की सहयोगी वितरण निगमों द्वारा रु0 18885.48 करोड़ की लागत से लगभग 2.69 करोड़ कन्ज्यूमर मीटर, 15.26 लाख डीटी मीटर एवं लगभग 20,000 फीडर मीटर की स्थापना का कार्य कराया जाना लक्षित है।

(8) प्रदेश में विद्युत लाइन लॉस को कम करने के लिए सभी डिस्कॉमों में रु 0 16,498.61 करोड़ की लागत का कार्य स्वीकृत। इन कार्यों की अद्यतन प्रगति 47 प्रतिशत है।

(9) विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए रिवैम्प्ड (आरडीएसएस)

योजना के तहत विद्युत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा।

(10) निजी नलकूप हेतु कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति किये जाने का निर्णय। किसानों को सिंचाई हेतु निर्गत वर्ष 2022-23 के विद्युत बिल के सरचार्ज में माफी योजना लागू। 19 जुलाई 2024 तक 5,44,088 उपभोक्ताओं द्वारा उक्त योजना में पंजीकृत कराया गया एवं अब तक रु 0 268 करोड़ की राजस्व प्राप्ति। 10,54,009 नलकूपों पर मीटर स्थापित किया गया।

(11) झटपट पोर्टल, निवेश मित्र पोर्टल आदि से 29,06,184 उपभोक्ताओं को नये संयोजन निर्गत किये गये एवं 30,97,666 उपभोक्ताओं के लोड में वृद्धि की गई।

(12) राजस्व वसूली के दृष्टिगत वर्ष 2023-24 में वर्ष 2022-23 से 23.98 प्रतिशत बढ़कर रु0 103600.48 करोड़ की गई।

(13) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं को एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा।

(14) उपभोक्ताओं को घर बैठे स्वयं अपना बिल बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम द्वारा मीटर की रीडिंग डालकर बिल बनाने की सुविधा। निगम में ईआरपी प्रणाली लागू।

(15) वित्तीय वर्ष 2023-24 में विद्युत गृहों द्वारा कुल 39583.993 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया। चालू वित्तीय वर्ष में माह जून तक कुल 12010.954 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 39,691 मिलियन यूनिट का सकल विद्युत उत्पादन कर नया कीर्तिमान स्थापित।

(16) फरवरी 2023 में सम्पन्न ग्लोबल इन्वेस्ट्र्स समिट में उ0प्र0 सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लि0 के साथ एमओयू हस्ताक्षरित।

(17) ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण। पारेषण तंत्र की क्षमता में वृद्धि करते हुए वर्ष 2023-24 में 28,900 मेगावॉट तथा वर्ष 2024-25 में पारेषण क्षमता बढ़ाकर 32,400 मेगावॉट किया जाना है।

(18) उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा दिनांक 13 जून, 2024 को 30618 मेगावॉट की उच्चतम मांग को सफलतापूर्वक वहन किया गया।

(19) यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में हुए एम0ओ0यू0 के तहत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में रु0 7899 करोड़ लागत की 135 अदद बायो एनर्जी परियोजनाओं तथा रु0 60,243 करोड़ की लागत की 44 अदद सौर ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा चुका है। यूटीलिटी स्केल पावर प्रोजेक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत 2500 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाओं का स्थापना कार्य पूर्ण।

(20) रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट के तहत 364 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित। हर घर सोलर अभियान के तहत जनपद वाराणसी में 28000 घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना हेतु रजिस्ट्रेशन। सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1,45,687 संयंत्रों, सौभाग्य योजना के तहत दूरस्थ ग्रामों में 53,354 तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत 7865 सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना।

(21) सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत आगामी 05 वर्षों में 22 हजार मेगावॉट विद्युत उत्पादन

क्षमता का लक्ष्य निर्धारित।

(22) उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के तहत कृषि व पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड अपशिष्ट आदि विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लाण्ट, बायो-कोल, बायो डीजल व बायो एथेनॉल की इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन। रु 0 1790 करोड़ के 32 निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति।

17. श्रम एवं सेवायोजन :-

(1) उ0प्र0 कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग का गठन। आउटसोर्सिंग आफ मैनपावर के लिए जेम पोर्टल पर पंजीकृत एवं बिड अवॉर्डी सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रक्रिया के निर्देश जारी।

(2) प्रदेश के सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों के हॉट स्पॉट को चिन्हित करते हुए 1197 ग्राम पंचायतों/शहरी वॉर्डों को बालश्रम मुक्त घोषित कर नया सवेरा योजना का संचालन, जिनमें 06 से 14 आयु वर्ग के 35,203 बच्चों तथा 15 से 18 आयु वर्ग के 14,837 कामकाजी बच्चों की पहचान कर औपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया। चिन्हित कामकाजी बच्चों के 12,266 परिवारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना से आच्छादित किया गया।

(3) श्रमिकों के कल्याणार्थ योजनाएं संचालित। कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 05 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता पर 04 लाख रुपये एवं आंशिक दिव्यांगता पर 03 लाख रुपये की सहायता।

(4) ई-श्रम पोर्टल पर वर्तमान में कुल 8.34 करोड़ कामगारों का पंजीकरण।

(5) एन0पी0एस0 ट्रेडर्स के अन्तर्गत अब तक कुल 13,053 कामगारों का पंजीयन कराकर उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान पर।

(6) प्रदेश के 9000 मजदूरों के लिए इजराइल में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए समन्वित किया गया। इससे प्रतिमाह लगभग रु0 90 करोड़ और प्रतिवर्ष रु0 1080 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

(7) कौशल प्राप्त कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं जनसामान्य को स्थानीय सेवाएं प्रदान करने हेतु सेवामित्र पोर्टल की व्यवस्था। सेवायोजन विभाग द्वारा 48,912 कुशल कामगारों, 875 सेवा प्रदाताओं, 4,664 सेवामित्रों की व्यवस्था की गई है। मिशन रोजगार के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागों द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर की गई प्रविष्टि के अनुसार रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त श्रमिकों/अभ्यर्थियों की संख्या 49,93,940 एवं सृजित मानव दिवस 17,76,26,400 है। कुल 7,841 रोजगार मेलों का आयोजन करते हुए 10,50,097 अभ्यर्थियों का चयन करते हुए सेवायोजित कराया गया।

(8) श्रमिकों के बच्चों एवं कोविड से अनाथ हुये बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा देने हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ।

(9) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत अब तक 6.79 लाख से अधिक कामगारों का पंजीकरण कराकर उत्तर प्रदेश सम्पूर्ण देश में द्वितीय स्थान पर है।

18. शिक्षा :-

(1) प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 01 से 08 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों एवं कार्यपुस्तिकाओं के साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी। शैक्षिक सत्र 2024-2025 से कक्षा 01 व 02 हेतु एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी।

(2) प्रदेश के 648 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को कक्षा 12 तक उच्चीकृत किया गया है। 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाएं एवं मानव संसाधन सुनिश्चित किया गया। इन विद्यालयों में 80,425 छात्राएं नामांकित हैं।

(3) सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान, डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने तथा अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के 2,09,863 शिक्षकों टैबलेट उपलब्ध कराये गये।

(4) परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 2 सेट यूनीफार्म, जूता-मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी के क्रय हेतु बच्चों के माता-पिता/अविभावक के खातों में रु0 1200 की धनराशि अन्तरित की गई।

(5) परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को निरन्तर सुदृढ़ किया जा रहा है। इस हेतु आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालयों में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्तीकरण किया जा रहा है।

(6) समेकित शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के 06-14 आयु वर्ग के समस्त दिव्यांग बच्चों को गुणवत्तापरक समावेशी शिक्षा के लिए दिव्यांग बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन एवं ऑनलाइन ट्रैकिंग हेतु 'समर्थ' मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन एवं पोर्टल विकसित किया गया है। समर्थ ऐप पर 2,97,851 दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर मुख्यधारा से जोड़ा गया।

(7) 'निपुण भारत मिशन' के अन्तर्गत शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष बल देते हुए शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न शैक्षणिक सामग्री यथा-आकर्षक पोस्टर्स, वार्तालाप चार्ट, बिग बुक्स, पिक्चर स्टोरी कार्ड, गणित अभ्यास कार्ड, टी0एल0एम0 गणित किट, विज्ञान किट, लाइब्रेरी बुक्स, तालिकायें आदि समस्त परिषदीय विद्यालयों को उपलब्ध करायी गयी है। निपुण विद्यालय का लक्ष्य हासिल करने वाले विद्यालय को रु0 25,000 की विशेष धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

(8) प्रदेश के 57 जनपदों में अटल आवासीय विद्यालयों की भांति मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय के निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन। पी०एम० श्री योजनान्तर्गत प्रदेश के 1,707 बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को चयनित किया गया। 351 परिषदीय कम्पोजिट विद्यालयों को मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किये जाने की कार्यवाही।

(9) प्रदेश में वर्तमान में कुल 28,794 माध्यमिक विद्यालय संचालित, जिसमें 2542 राजकीय,

4510 अशासकीय सहायता प्राप्त तथा 21742 वित्त विहीन अशासकीय विद्यालय सम्मिलित हैं। संस्कृत शिक्षा के लिए कुल 1240 विद्यालय संचालित। अब तक 60 नये राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्वीकृति। 356 नये राजकीय इण्टर कॉलेज/हाईस्कूल का संचालन तथा 77 बालिका छात्रावास का संचालन। 41 नये इण्टर कॉलेज व 215 राजकीय हाईस्कूल तथा 77 बालिका छात्रावासों के भवन निर्माण पूर्ण।

(10) 757 राजकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा व्यवस्था तथा कम्प्यूटर शिक्षा हेतु आईसीटी लैब की स्थापना। 645 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ। 101 राजकीय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना।

(11) असेवित बस्ती के चिन्हीकरण में सहायता हेतु 'पहुँच पोर्टल', विद्यार्थियों की कैरियर गाइडेन्स हेतु 'पंख पोर्टल', ई-लाइब्रेरी हेतु 'प्रज्ञान पोर्टल', विद्यालय ऑनलाइन अनुश्रवण श्रेणीकरण हेतु 'परख पोर्टल', विद्यालयों के वेबपेज/वेबसाइट हेतु 'पहचान पोर्टल' विकसित। विद्यार्थियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 'प्रवीण योजना' का संचालन। संसाधन मैपिंग के लिए 'प्रोजेक्ट अलंकार पोर्टल' विकसित।

(12) यू0पी0 बोर्ड परीक्षा प्रथम बार 12 कार्य दिवसों में सम्पन्न करायी गयी।

(13) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के सुदृढीकरण योजनान्तर्गत इसे व्यवसायपरक बनाने हेतु इसमें आधुनिक विषयों का समावेश एवं एन0सी0ई0आर0टी0 की पाठ्य पुस्तके लागू। रोजगारपरक शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा 04 डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ।

(14) प्रदेश में कुल 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 149 आईटीआई के उन्नयन का कार्य प्रारम्भ। राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण/प्रमाणीकृत 1.96 लाख सफल प्रशिक्षार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों/अधिष्ठानों में कैम्पस प्लेसमेंट/रोजगार मेलों के माध्यम से सेवायोजित कराया गया।

(15) वर्तमान में डिप्लोमा स्तरीय 147 राजकीय एवं 19 अनुदानित तथा 18 संस्थाएं पी0पी0पी0 मोड सहित कुल 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 89 पॉलीटेक्निकों में लैंग्वेज लैब तथा 183 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना। छात्र-छात्राओं की समस्याओं का ऑनलाइन निराकरण हेतु Students Grievance Call का गठन। 20 महिला छात्रावास का निर्माणाधीन।

(16) प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प के दृष्टिगत उद्योगों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में दक्ष मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए सत्र 2022-23 से न्यू एज कोर्स के अंतर्गत एक वर्षीय 4 नवीन पाठ्यक्रम यथा पीजी डिप्लोमा इन डाटा साइन्स एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रारम्भ।

(17) उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, जिसमें 134 विषयों के 77,000 कन्टेंट उपलब्ध हैं।

(18) प्रदेश सरकार द्वारा 03 नये राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय को रु0 38.53 करोड़ एवं मुरादाबाद मण्डल में राज्य

विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु रु0 33.47 करोड़ की धनराशि निर्गत। देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर के भवनों के निर्माण हेतु रु0 33.47 करोड़ की धनराशि निर्गत।

(19) मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से आच्छादित 52 नये राजकीय महाविद्यालयों तथा एक राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की स्थापना। राज्य सेक्टर के अंतर्गत 76 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर। 83 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 712 प्रवक्ताओं, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कुल 4,804 प्रवक्ता, 290 प्राचार्य की नियुक्ति।

19. समाज कल्याण :-

(1) ''मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना'' के अंतर्गत प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार हेतु निःशुल्क ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब तक कुल 63,057 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(2) वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के तहत 56 लाख पेंशनरों को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है।

(3) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में धनराशि रु0 2,36,518.88 लाख का व्यय करते हुए अब तक 7,88,396 परिवारों को आर्थिक सहायता।

(4) समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों के शैक्षिक उत्थान हेतु प्रदेश में कुल 101 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्ववर्ती नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) संचालित, जिसमें वर्ष 2024-25 में 32,683 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत।

(5) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब तक 3,82,232 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया। योजना के तहत अनुदान राशि 35 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये करते हुए लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(6) प्रदेश के 75 जनपदों में 150 संवासियों की क्षमता के वृद्धाश्रम संचालित। इसके माध्यम से अब तक 47,094 वृद्ध लाभान्वित।

(7) पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के 3,74,963 छात्र-छात्राओं को, सामान्य वर्ग के 1,35,644 छात्र-छात्राओं को तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना के अंतगर्त 2023-24 में अनुसूचित जाति के 10,33,599 छात्र-छात्राओं को तथा सामान्य वर्ग के 6,18,164 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति /शुल्कप्रतिपूर्ति वितरित।

(8) पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7,58,044 छात्र-छात्राओं के खातों में रु0 160.16 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित। दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 19,58,929 छात्र-छात्राओं को रु0 2026.73 करोड़ की धनराशि उनके खातों में हस्तान्तरित।

(9) पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान। वित्तीय वर्ष 2023-24 में

52,553 लाभार्थियों के खाते में रु0 105.11 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित।

(10) पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए ओ-लेवल व सी 0सी0सी0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 23,697 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(11) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हेतु निर्माणाधीन कुल 1218 परियोजनाओं के सापेक्ष माह जनवरी, 2024 तक 539 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

(12) अल्पसंख्यक पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 1,02,337 छात्र-छात्राओं को रु0 2999.98 लाख एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2023-24 में 2,47,709 छात्र-छात्रओं को रु0 18999.99 लाख की धनराशि वितरित। हज-2023 में कुल 24,788, हज-2024 में अब तक कुल 9,465 हज यात्री हज पर भेजे गये। हज यात्रियों के सहयोग हेतु 30 हज सेवकों को भी भेजा गया।

(13) प्रदेश में 10,37,620 दिव्यांगजनों को 1000 रु0 प्रतिमाह की दर से दिव्यांग भरण पोषण अनुदान/पेंशन तथा 11,551 लाभार्थियों को 3000 रु0 प्रतिमाह की दर से कुष्ठावस्था पेंशन वितरित।

(14) वित्तीय वर्ष 2023-24 अब तक कुल 31,536 दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों का वितरण। शल्य चिकित्सा अनुदान के अंतर्गत 41 करेक्टिव सर्जरी एवं 124 श्रवण बाधित बच्चों की कॉक्लियर इम्प्लाण्ट सर्जरी की गई। दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कुल 1045 दिव्यांगजन लाभान्वित हुए।

(15) डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में 4696 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। दिव्यांगजन की उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट में जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्व विद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिस्थापित।

20. महिला एवं बाल विकास :-

(1) राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत कुल 93,658 बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावकों से मिलाया गया तथा 1,707 सम्भावित बाल विवाह रोके गये। 1645 बालकों को अब तक दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वासित किया गया।

(2) बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु ''मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना'' लागू, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी बालिका को 25,000 रु0 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जाता है। अब तक 19.34 लाख पात्र बालिकायें लाभान्वित।

(3) बेटी-बचाओ, बेटी-पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में कुल 23,184 गतिविधियों के माध्यम से 26.60 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूक किया गया।

(4) '181' महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत अब तक 7.17 लाख महिलाओं/बालिकाओं को सहायता प्रदान की गई।

(5) वन स्टॉप सेन्टर योजना के अंतर्गत कुल 1.82 लाख मामले संदर्भित किये गये हैं।

(6) मिशन शक्ति अभियान के तहत लगभग 9 करोड़ पुरुष/महिला/अन्य को जागरूक किया गया। जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु ''रानी लक्ष्मीबाई

बाल एवं महिला सम्मान कोष'' की स्थापना। इस योजना के अंतर्गत कुल 8,197 महिलाओं तथा बालिकाओं को क्षतिपूर्ति धनराशि दी गई।

(7) पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत 32.71 लाख निराश्रित महिलाओं को 1000 रुपये मासिक की दर से पेंशन दी जा रही है।

(8) प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुये बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि में आर्थिक सहयोग हेतु ''उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना'' के अंतर्गत 13,643 बच्चों को 4,000 रु0 प्रतिमाह तथा 5,068 बच्चों को लैपटॉप वितरित। ''उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)'' के अंतर्गत 47,234 बच्चों को 2,500 रु0 प्रतिमाह आर्थिक सहायता सहित आदि सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

21. राजस्व :-

(1) स्वामित्व योजना के अंतर्गत 90,573 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए 22 जुलाई, 2024 तक कुल 62,214 ग्रामों में 86,62,801 घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 23821 लाभार्थी लाभान्वित हुए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24000 से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाएगा।

(2) अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश स्तर पर 4 स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन। प्रदेश में एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित कुल 3,83,331 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 3,81,458 शिकायतें निस्तारित। अभियान के अंतर्गत कुल 67161.64 हे0 भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी तथा 24,470 राजस्व वाद, 1,110 सिविल वाद व 4,718 एफआईआर दर्ज कराते हुए 1,587 अतिक्रमणकारियों को भू-माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए वैधानिक कार्यवाही की गई। वर्तमान में 212 भू-माफिया जेल में निरुद्ध।

(3) 1,110 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध आई0पी0सी0 के अंतर्गत, 260 के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, 06 के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत; 85 के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत, 323 के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अंतर्गत तथा 3,140 के विरुद्ध अन्य धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।

22. परिवहन :-

(1) माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा देश के विभिन्न जनपद मुख्यालयों को जोड़ते हुए राज्य की राजधानी एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हेतु परिवहन सेवाओं का शुभारम्भ किया है। वर्तमान में 97 बसें लखनऊ राजधानी एक्सप्रेस सेवा एवं दिल्ली हेतु 91 बसें राजधानी दिल्ली एक्सप्रेस सेवा के रूप में संचालित हैं। परिवहन निगम के बस बेड़े में वृद्धि किये जाने तथा पुरानी बसों को प्रतिस्थापित किये जाने हेतु बसों के क्रय हेतु प्राप्त धनराशि से 1425 नई डीजल बीएस-6 बसों को बस बेड़े में शामिल किया गया तथा 1350 नई बसों की बाडी निर्माण प्रक्रियाधीन।

(2) निगम द्वारा अपनी बस सेवाओं में सीटों के अग्रिम आरक्षण, डिजिटल माध्यम से भुगतान करने व फीडबैक हेतु यूपी राही ऐप का अनावरण।

(3) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 अक्टूबर, 2023 को अयोध्या में मिशन महिला सारथी

अभियान के शुभारम्भ के साथ ही 51 बीएस-6 बसों का शुभारम्भ किया। वर्तमान में 38 बस स्टेशनों के निर्माण व उच्चीकरण का कार्य प्रगति पर।

(4) बसों में 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा व्यवस्था के लिए निगम को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में रु0 1 करोड़ की धनराशि का प्राविधान तथा परिवहन निगम द्वारा महिलाओं के लिए 50 पिंक सेवाओं का संचालन।

(5) सभी बसों में गति नियंत्रण हेतु स्पीड कन्ट्रोल डिवाइस स्थापित। दिव्यांग सशक्तीकरण के अंतर्गत 202 बस स्टेशनों पर व्हील चेयर, रैम्प, रेलिंग, प्रसाधनों आदि की व्यवस्था। सुरक्षित संचालन एवं दुर्घटना की प्रभावी रोकथाम के दृष्टिगत चालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण कर चालक स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड बनाया गया तथा नशे की रोकथाम के लिए निरीक्षक दल को ब्रेथ एनेलाइजर उपकरण दिये गये।

(6) रक्षाबन्धन पर्व पर वर्ष 2023 में 29.30 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई। 50 बस स्टेशनों पर नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु माताओं के लिए शिशु देखभाल कक्ष की व्यवस्था।

<u>23. सड़क एवं यातायात योजना (लोक निर्माण विभाग) :-</u>

(1) वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 30,416 किमी. लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण। अब तक लगभग 23,628 किमी0 लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण। 02 लेन मार्ग बनाने/चौड़ीकरण करते हुए 162 विकास खण्ड मुख्यालयों को जोड़ने हेतु 1378 किलोमीटर लम्बाई हेतु रु0 2338 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, 143 कार्य पूर्ण तथा 26 तहसील मुख्यालयों को 02 लेन मार्ग से जोड़ने हेतु लम्बाई 270 किलोमीटर चौड़ीकरण हेतु रु0 391 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत, 26 कार्य पूर्ण।

(2) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत राजस्व ग्रामों एवं मजरों में कुल 181 मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण।

(3) 238 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण तथा 100 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन हेतु चालू। 883 लघु सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण। इसके अतिरिक्त 225 दीर्घ सेतु, 594 लघु सेतु एवं 179 रेल उपरिगामी सेतु कुल 998 सेतु निर्माणाधीन।

(4) प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जनसामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1,202 किमी0 लम्बाई की 102 सड़कों में से 86 सड़कों का निर्माण पूर्ण।

(5) वर्ष 2023-24 में 44,382 किमी0 तथा वर्ष 2024-25 में अब तक 11,862 किमी0 लम्बाई की सड़कों को गड्ढामुक्त/नवीनीकरण किया गया।

(6) सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए अब तक लगभग 792.64 किमी0 लम्बाई की स्वीकृत 466 सड़कों का नवीन तकनीक से प्लास्टिक मार्ग का निर्माण।

(7) लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए प्रतिदिन 09 किलोमीटर के औसत से चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत से नये मार्गों का निर्माण तथा औसतन प्रत्येक दो दिन में एक सेतु का निर्माण पूर्ण किया जा रहा है।

(8) प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों की श्रेणी परिवर्तित करते हुए कुल 70 नये राज्य मार्ग लम्बाई 5604 किमी0 तथा जनपद के विकास एवं स्थलीय यातायात के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण 57 नये प्रमुख जिला मार्ग लम्बाई 2831 किमी0 घोषित करते हुए दो लेन चौड़ा करने का कार्य किया जायेगा।

(9) मार्ग सुरक्षा/यातायात सुरक्षा हेतु चिन्हित 567 ब्लैक स्पॉट में से 321 ब्लैक स्पॉट का सेफ्टी आडिट आईआईटी दिल्ली तथा 246 का आईआईटी बीएचयू द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ब्लैक स्पॉट के सुधार की कार्ययोजना प्रक्रियाधीन।

(10) विभाग की टेण्डर प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने हेतु प्रहरी एप्लीकेशन को लागू किया गया। पारदर्शिता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए लोक निर्माण विभाग के बजट, पंजीकरण, ई-एमबी, ई-बिलिंग, ई-डिमाण्ड, ई-एलाटमेन्ट को ऑनलाइन करने के लिए ''चाणक्य'' एवं ''विश्वकर्मा'' नाम से दो बड़े साफ्टवेयर लागू।

24. पंचायतीराज :-

(1) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रथम चरण में 2.18 करोड़ शौचालय निर्माण के साथ प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त/ओडीएफ घोषित किया गया। सर्वाधिक शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(2) ओडीएफ प्लस मानक श्रेणी के तहत ओडीएफ प्लस ग्रामों को तीन श्रेणियों/चरणों उदीयमान, उज्ज्वल एवं उत्कृष्ट में विभक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में चयनित ग्रामों/ग्राम पंचायतों के प्रधान, सचिव, पंचायत सहायक, सफाईकर्मी, राजगीर, डीसी, डीपीआरओ, डीडीपी एवं राजमिस्त्रियों सहित कुल लगभग 1.12 लाख से अधिक स्टेकहोल्डर्स को प्रशिक्षित किया गया है।

(3) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का द्वितीय चरण वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में 17,23,444 व्यक्तिगत शौचालय एवं वर्ष 2024-25 में लक्षित 16,17,535 के सापेक्ष 1,03,699 व्यक्तिगत शौचालय निर्मित तथा प्रदेश की 57,691 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया।

(4) ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन अन्तर्गत 8,43,352 सामुदायिक खाद गड्ढे तथा 16,81,343 सामुदायिक सोख्ता गड्ढे का निर्माण कराया गया। गोबरधन परियोजना के तहत 58 जनपदों में 102 योजना का कार्य पूर्ण। प्लास्टिक प्रबन्धन के लिए 45 पी0डब्लू0एम0 यूनिट का कार्य पूर्ण।

(5) पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना केन्द्र पुनरोधित योजना के रूप में संचालित। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु भारत सरकार द्वारा 368.97 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत की गई। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में कुल रु0 165 करोड़ की धनराशि अवमुक्त।

(6) 51,515 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवालयों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना के माध्यम से पंचायत में लगभग रु0 2.40 करोड़ आय का सृजन कराया गया। डिजिटल लेन-देन

को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के कुल 57,702 ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों में यू0पी0आई0 आई0डी0 एवं क्यू0आर0 कोड की स्थापना करायी गयी। प्रथम बार जेमपोर्टल का इंटीग्रेशन, भारत सरकार के साफ्टवेयर ई-ग्राम स्वराज से करते हुए ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन क्रय प्रणाली से जोड़े जाने की कार्यवाही की गयी, जिसके तहत 7,289 ग्राम पंचायतें जेम पोर्टल पर पंजीकृत।

(7) प्रदेश को ई-गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्यों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(8) प्रिट द्वारा महिला प्रधानों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल एवं लैंगिक समानता विषय पर पहली बार पृथक से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 11,814 महिला प्रधानों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(9) पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों हेतु प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने हेतु मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित। इस योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचत सदस्यों की पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार/आश्रित के सहायतार्थ पंचायत कल्याण कोष की स्थापना। इस कोष के अंतर्गत 1,408 आवेदकों के परिवारों को सहायता राशि दी गई।

25. पर्यटन एवं संस्कृति :-

(1) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में जनवरी से दिसम्बर तक कुल 48,01,27,191 पर्यटक आये, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 47,85,25,688 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 16,01,503 थी। वर्ष 2024 में जनवरी से मई तक अनुमानित कुल 16,86,34,732 पर्यटक आये, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 16,76,81,521 एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 9,53,211 है।

(2) जनपद अयोध्या में चौदह कोसी मार्ग पर पर्यटक सुविधा की स्थापना का कार्य 1210.72 लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

(3) जनपद अयोध्या सदर स्थित अफीम कोठी का पर्यटन विकास कार्य 1452.51 लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

(4) जनपद अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित पर्यटन स्थल (कुण्डों) का पर्यटन विकास निर्माण कार्य 1772.01 लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

(5) जनपद कुशीनगर बुद्धा थीम पार्क की परियोजना का कार्य 1734.88 लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

(6) जनपद अमेठी की नगर पालिका परिषद जायस स्थित बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली का पर्यटन विकास 1849.97 लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

(7) जनपद लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण 2295.22 लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

(8) जनपद वाराणसी के रामनगर स्थित शास्त्री घाट का निर्माण 1055.86 लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

(9) जनपद फिरोजाबाद के आर्य गुरूकुल महाविद्यालय सिरसागंज में सांस्कृतिक काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य 2424.45 लाख रुपये की धनराशि से कराया जा रहा है।

(10) जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में ललिता देवी मंदिर के समीप 1522.92 लाख की लागत से काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

(11) जीआईएस समिट-2023 में उद्यमियों के साथ पर्यटन विभाग द्वारा 1,163 एमओयू निष्पादित किये गये, जिसके द्वारा प्रदेश में 1,52,150 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना है, इससे 3,72,114 रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

(12) पर्यटन नीति-2022 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु विभागीय पोर्टल पर 715 पर्यटन इकाइयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी।

(13) मा0 मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 01 पर्यटन स्थल विकसित किये जाने की कार्य योजना।

(14) उ0प्र0 ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ रुपये की धनराशि से 27 परियोजनाओं का विकास कार्य कराया जा रहा है।

(15) देश की समृद्ध सांस्कृतिक, अध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरूक करने के लिए युवा पर्यटन क्लब का गठन।

(16) ग्रामीण पर्यटन के तहत 75 ग्रामों को 02 वर्ष की अवधि में ग्राम्य पर्यटन हेतु चयन कर पर्यटन का विकास किया जाना प्रस्तावित। ग्रामों को पर्यटकों के लिए सतत आकर्षण का केन्द्र बनाने के लिए 229 गांव चयनित।

(17) उ0प्र0 श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद, उ0प्र0 श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद तथा उ0प्र0 श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन।

(18) दीपोत्सव अयोध्या-छोटी दीपावली के अवसर पर 11 नवम्बर, 2023 को राम की पैड़ी पर 22,23,000 दीप जलाकर वर्ल्ड रिकार्ड कायम किया गया। काशी में देवदीपावली का आयोजन , मथुरा में कृष्ण उत्सव एवं बृजरज उत्सव का आयोजन।

(19) पर्यटकों की सुविधा एवं सुरक्षा हेतु पर्यटन पुलिस का गठन।

(20) राज्य सरकार द्वारा रोप-वे परियोजना पीपीपी मॉडल पर जनपद-चित्रकूट एवं अष्टभुजा-कालीखोह में शुरू।

(21) आगरा एवं मथुरा हेलीपोर्ट को पीपीपी मोड पर संचालित किये जाने के लिए निजी निवेशक का चयन।

(22) अयोध्या, वाराणसी एवं नेमिषारण्य हेली पोर्ट को पीपीपी मोड पर विकसित एवं संचालित करने के लिए मा0 मत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त।

(23) 11 पर्यटक आवास गृहों को निजी निवेशकों के साथ पीपीपी मोड पर विकसित एवं संचालित करने के लिए अनुबन्ध निष्पादित।

(24) प्रदेश का संस्कृति विभाग प्रचार-प्रसार एवं विभिन्न अवसरों पर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति एवं लोक कलाओं को संवर्धित एवं संरक्षित कर रहा है।

(25) अयोध्या रामोत्सव-2024 के अंतर्गत 14 जनवरी से 24 मार्च 2024 तक अयोध्या के

05 बड़े मंचों तथा 15 छोटे मंचों के माध्यम से 10,000 कलाकारों द्वारा भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति।

(26) उ0प्र0 दिवस के अवसर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले दो महानुभावों को उ 0प्र0 गौरव सम्मान-2024 से सम्मानित किया गया।

(27) मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इमलिया कोडर जनपद बलरामपुर में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का निर्माण।

(28) लखनऊ में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय का निर्माण व गोरखपुर तथा मेरठ संग्रहालय का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया गया।

(29) पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक ग्राम बटेश्वर , आगरा में सांस्कृतिक संकुल का लोकार्पण।

(30) सार्वजनिक रामलीला स्थलों की चहारदीवारी का निर्माण।

(31) लखनऊ में उ0प्र0 सांस्कृतिक संग्रहालय का निर्माण तथा जनपद आजमगढ़ में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय का निर्माण।

(32) वृद्ध एवं निर्धन कलाकारों को मासिक पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में जीवित प्रमाण पत्र के आधार पर 393 कलाकारों को पेंशन।

(33) श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जनपद मैनपुरी जेल चौराहे पर 12.5 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा की स्थापना।

(34) गोण्डा तथा बाराबंकी में पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की 06 फीट आदमकद कांस्य प्रतिमायें स्थापित।

(35) जनपद फिरोजाबाद के सिरसागंज तथा ककरऊ कोठी में महाराणा प्रताप की 12.5 फीट अश्वारोही कांस्य प्रतिमा की स्थापना।

(36) वाद्ययंत्र वितरण योजना के अंतर्गत प्रदेश की ग्राम पंचायतों को सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु 450 वाद्ययंत्रों का 1-1 सेट वितरित।

(37) एडाप्ट-ए-हेरिटेज पॉलिसी के अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मार्कों हेतु स्मारक मित्र बनाये गये।

(38) भातखण्डे सम विश्वविद्यालय को संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

(39) ग्लोबल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण प्रोजेक्ट के अंतर्गत अयोध्या शोध संस्थान द्वारा 10 ग्रंथों का प्रकाशन।

<u>26. ग्राम्य विकास, दुग्ध, पशुधन व मत्स्य विभाग :-</u>

(1) उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 8,54,266 स्वयं सहायता समूहों, 52,262 ग्राम संगठनों एवं 2,835 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए 95 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आच्छादित किया गया है।

(2) ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने हेतु बी0सी0 सखी योजना के अंतर्गत लगभग 50,192 बी0सी0 सखी का प्रमाणीकरण पूर्ण किया गया , जिसमें 38,844 बी0सी0

सखी द्वारा कार्य करते हुए रु0 25,505 करोड़ से अधिक का वित्तीय लेन-देन किया गया व लगभग 68.43 करोड़ रु0 का लाभांश अर्जित किया गया।

(3) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक कुल 36.15 लाख आवास आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 35.75 लाख आवास पूर्ण। शेष निर्माणाधीन।

(4) मुख्यमंत्री आवास (ग्रामीण) योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 2.57 लाख आवास निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 2.49 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण।

(5) मनरेगा में मानव दिवस सृजन में वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिला सहभागिता 43 प्रतिशत है, 18.06 लाख महिला श्रमिकों को मिला रोजगार।

(6) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में गत वर्षों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

(7) मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,600 लाख मानव दिवस का सृजन निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 08 जुलाई 2024 तक 1027.28 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए रु0 2556.42 करोड़ की धनराशि व्यय एवं 37.80 लाख परिवारों को मिला रोजगार।

(8) प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में 02 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य। 23,788 चिन्हांकित अमृत सरोवरों में 17,603 अमृत सरोवर पर कार्य पूर्ण। अमृत सरोवर के निर्माण कार्य में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।

(9) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-तृतीय के अंतर्गत स्वीकृत 2,494 मार्गों एवं 4 पुल के सापेक्ष 1,944 मार्गों एवं 4 लम्बे स्पान के पुलों का निर्माण पूर्ण। शेष मार्ग निर्माणाधीन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा 4034 किमी0 के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1127.71 किमी0 सड़कों का निर्माण पूर्ण।

(10) प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु कार्य प्रगति पर।

(11) उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के अंतर्गत 3,237 प्रोजेक्ट के एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराये गये हैं, जिनमें 563 इकाइयों के प्रोजेक्ट जी0बी0सी0 से स्वीकृत हैं, जिसके द्वारा 2106.39 करोड़ का निवेश होगा। 1,23,439 व्यक्तियों को स्वरोजगार प्राप्त होगा।

(12) नन्दबाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विभिन्न कमेटियों का गठन। समस्त जनपदों में सहकारी डेयरियों में सर्वाधिक दुग्ध आपूर्ति करने वाले उत्पादक सदस्य को प्रोत्साहन के रूप में गोकुल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

(13) दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत पशुपालन के लिए माह मार्च 2024 तक 553071 किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को निर्गत।

(14) प्रदेश में गोसंरक्षण के लिए कुल 7490 अस्थायी/स्थायी गोवंश आश्रय स्थल स्थापित, इनमें 14,97,943 निराश्रित गोवंश संरक्षित।

(15) प्रदेश सरकार द्वारा लम्पी स्किन बीमारी की रोकथाम हेतु किये गये प्रयासों की सराहना

भारत सरकार द्वारा की गयी एवं प्रदेश के मॉडल को अन्य प्रदेशों में भी अपनाया गया। इस बीमारी की प्रभावी रोकथाम हेतु पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब तक इस बीमारी से बचाव हेतु 01 करोड़ 58 लाख गोवंश का टीकाकरण किया जा चुका है।

(16) कुक्कुट विकास नीति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 93 इकाइयों की स्थापना हेतु एल0ओ0सी0 निर्गत। कुक्कुट विकास नीति 2022 के अंतर्गत अभी तक रु0 242 करोड़ का निवेश, जिससे 9780 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

(17) बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना में 22,801 ब्रायलर पालन इकाइयां स्थापित करायी जा रही हैं।

(18) वर्ष 2023-24 में प्रदेश में अब तक 9.39 मै0टन मत्स्य उत्पादन। उत्तर प्रदेश को भारत सरकार से देश का सर्वश्रेष्ठ अर्न्तस्थलीय मात्स्यिकी राज्य का पुरस्कार प्राप्त।

(19) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत प्रारम्भ से अब तक रु0 292 करोड़ का अनुदान लाभार्थियों को वितरित। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 625 हे0 जलक्षेत्रों में मत्स्य पालन निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक की स्थापना हेतु लगभग 687 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा। सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत अब तक 1,16,194 मछुआरों/मत्स्य पालकों को किया गया आच्छादित।

(20) निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत 05 करोड़ रुपये के बजट का प्राविधान, जिसके तहत 1865 मछुआरों को लाभान्वित किया गया। 15,212 मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध। प्रदेश में सदानीरा नदियों पर मत्स्य आखेट हेतु मछुआ समुदाय की मत्स्य जीवी सहकारी समितियां बनाने हेतु नई नीति का निर्धारण।

27. वन एवं पर्यावरण :-

(1) 'पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ' जन अभियान-2024 के अन्तर्गत प्रदेश में 36.50 करोड़ वृक्षारोपण लक्ष्य के सापेक्ष 36.51 करोड़ पौध रोपित कर रिकार्ड बनाया गया। मा 0 मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में कुकरैल नदी के तट पर अतिक्रमण से मुक्त करायी गयी भूमि पर मा0 प्रधानमंत्री जी के आह्वान 'एक पेड़ माँ के नाम' के समादर में शक्ति-सौमित्र वन स्थापना स्थल पर मंत्रोच्चार के मध्य हरिशंकरी रोपित कर 'पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ' जन अभियान-2024 का शुभारम्भ किया।

(2) उत्तर प्रदेश में 223 महत्वपूर्ण वेटलैण्डस् के जलागम क्षेत्र में वेटलैण्ड संरक्षण वन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर वनो की स्थापना। प्रदेश के 35 सीमावर्ती जनपदों में 'मित्र वन' के अंतर्गत वृक्षारोपण। पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ जन अभियान- 2024 के अंतर्गत मियावाकी वन, सौमित्र वन, शक्ति वन, आयुष वन, पंचवटी, नवग्रह वाटिका की स्थापना व हरिशंकरी का वृहद स्तर पर रोपण किया गया। 'पवित्र धारा वृक्षारोपण' योजना के अंतर्गत लगभग 3.72 करोड़ पौधों का सघन वृक्षारोपण किया गया।

(3) उत्तर प्रदेश 10 वेटलैण्डस् के साथ देश का सर्वाधिक रामसर साइट घोषित राज्य।

(4) गोरखपुर वन प्रभाग के तिलकोनिया रेंज में आरोग्य वन की स्थापना की गयी है। यह

प्रदेश का पहला आरोग्य वन है। गोरखपुर में कैम्पियरगंज रेंज के अंतर्गत स्थापित "रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र" देश का पहला गिद्ध प्रजनन केन्द्र है।

(5) 100 वर्ष से अधिक ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक एवं महत्वपूर्ण अवसरों से जुड़े प्रदेश के 28 प्रजातियों के 948 वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया।

(6) राज्य पक्षी सारस की संख्या 19,918 हो गई।

(7) प्रदेश सरकार द्वारा 17 अक्टूबर, 2023 को गंगा डाल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया।

28. खेल, युवा कल्याण एवं कौशल विकास :-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती हेतु नियमावली प्रख्यापित। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 पदक विजेताओं को सीधे राजपत्रित पदों पर भर्ती की गई है, जिनमें 05 खिलाड़ियों को पुलिस उपाधीक्षक, 02 खिलाड़ियों को नायब तहसीलदार, 01 खिलाड़ी को यात्री/माल कर अधिकारी एवं 02 खिलाड़ियों को जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 479 कुशल खिलाड़ियों की आरक्षी पद पर नियुक्ति। शासकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण।

(2) ओलम्पिक गेम्स (एकल वर्ग) में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को रु 0 6 करोड़, रजत पदक विजेता को रु0 4 करोड़ तथा कांस्य पदक विजेता को रु0 2 करोड़ के पुरस्कार की व्यवस्था। ओलम्पिक गेम्स (टीम गेम्स) में स्वर्ण पदक विजेता को रु0 3 करोड़, रजत पदक पर रु0 2 करोड़ तथा कांस्य पदक पर रु0 1 करोड़ पुरस्कार की व्यवस्था। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता को रु0 3 करोड़, रजत पदक पर रु0 1.5 करोड़ तथा कांस्य पदक पर रु0 75 लाख के पुरस्कार की व्यवस्था। कॉमन वेल्थ गेम्स अथवा विश्वकप से जुड़ी प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक पर रु0 1.5 करोड़, रजत पदक पर रु0 75 लाख तथा कांस्य पदक पर रु0 50 लाख के पुरस्कार की व्यवस्था।

(3) प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 16 खेलों में 18 जनपदों में कुल 890 खिलाड़ियों को 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में उत्कृष्ट तकनीकी प्रशिक्षण। प्रदेश में 03 स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित।

(4) उत्तर प्रदेश राज्य खेल नीति-2023 लागू। एक जिला एक खेल योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में खेलो इण्डिया सेन्टर की स्थापना। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना, इसके लिए रु0 97.13 करोड़ की स्वीकृति निर्गत। वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के व्यापक विकास हेतु रु0 315 करोड़ की लागत से कार्य कराया जा रहा है।

(5) ग्रामीण स्तर पर अब तक कुल 83 स्टेडियम स्थापित। खेलो इण्डिया के अंतर्गत 21 परियोजनाएं स्वीकृत, 15 पूर्ण। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत 20 परियोजनाओं में से 10 पूर्ण। प्रदेश में पंचायत स्तर पर गठित 80,000 युवक/महिला मंगल दल को खेल प्रोत्साहन सामग्री देकर प्रोत्साहित किया गया।

(6) उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विगत 06 वर्षों में 13.89 लाख युवाओं को

निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर 5.40 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। एनएसडीसी के सहयोग से स्किल इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर वाराणसी द्वारा देश 2850 युवाओं को विदेशों में रोजगार हेतु चयनित किया गया है।

(7) मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 35 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के क्रम में 22 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण कार्य पूर्ण।

(8) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अवधारणा के अनुसार प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत छात्रों के मिशन प्रेरणा प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगारोंन्मुख व्यावसायिक/स्किल के प्रशिक्षण देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं मिशन के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षरित।

29. सूचना विभाग :-

(1) वर्तमान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी, विकासपरक, रोजगारपरक एवं महत्वपूर्ण योजनाओं, कार्यक्रमों का होर्डिंग, एलईडी, विज्ञापन, विभिन्न प्रकार के प्रकाशन, प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य, लेख, फीचर, सफलता की कहानी, प्रेस विज्ञप्तियों, सोशल मीडिया, फोटो, फिल्म आदि विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(2) उ0प्र0 फिल्म बन्धु/फिल्म विकास परिषद हेतु यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत सेक्टर-21 में लगभग 1000 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त फिल्म सिटी का निर्माण प्रक्रियाधीन। विकसित की जा रही फिल्म सिटी परियोजना के अंतर्गत प्रथम चरण में रु0 1410 करोड़ के प्रस्तावित निवेश से 230 एकड़ भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना का कार्य गतिमान।

(3) लोकभवन में मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं, नीतियों, उपलब्धियों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार।

30. खादी तथा ग्रामोद्योग :-

(1) मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 5606 इकाइयां स्थापित करते हुए 1,02,940 लोगों को रोजगार।

(2) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 25,717 इकाइयां स्थापित करते हुए 2,53,565 लोगों को रोजगार। पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 तथा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1,693 इकाइयों को लाभान्वित किया गया। पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत 892 संस्थाओं के 3,56,097 कत्तिन एवं बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

(3) सोलर चर्खा वितरण एवं प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत विगत 06 वर्षों में 5,377 लाभार्थियों को सोलर चर्खा वितरण कराते हुए 10,054 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया।

(4) मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 785 इकाईयों की स्थापना तथा 2,355 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

(5) माटीकला टूलकिट्स वितरण योजनान्तर्गत विगत पांच वर्षों में 14,140 लाभार्थियों को

तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिलाते हुए विद्युत चालित कुम्हारी चाक का वितरण। दोना पत्तल मेकिंग मशीन वितरण के अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक 1,449 अदद दोना पत्तल मशीनों का वितरण करते हुए 4347 व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ा गया।

31. भूतत्व एवं खनिकर्म :-

(1) खनिज सेवाओं के ऑनलाइन निस्तारण के लिए इन्टीग्रेटेड यूनीफाइड सिंगल इण्टर फेस "UP Mines Mitra" पोर्टल विकसित। मुद्रित परिवहन परिपत्र के स्थान पर ई-परिवहन प्रपत्र की व्यवस्था लागू।

(2) माइन मित्रा पोर्टल पर विकसित समाधानों के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 को डिजिटल इण्डिया एवॉर्ड-2022 (प्लैटिनम एवॉर्ड), 25वॉ नेशनल ई-गवर्नेंस एवॉर्ड-2022 (गोल्ड एवॉर्ड) एवं 19वॉ सीएसआईएसआईजी ई-गवर्नेंस एवॉर्ड-2021 प्राप्त हुआ।

(3) जन सामान्य हेतु ऑनलाइन नागरिक/किसान सेवाएं :- जिनमें कृषि भूमि , निजी भूमि, साधारण मिट्टी, भवन/विकास परियोजनाओं से निकले उपखनिजों के निस्तारण , भण्डारण लाइसेंस आदि के लिए 10 सेवाएं प्रदत्त। कुल 2,27,972 आवेदन निस्तारित।

(4) एकीकृत खनन निगरानी तंत्र के अंतर्गत कुल क्रियाशील 55 चेकगेट, कुल निर्गत नोटिस 1,32,024 के सापेक्ष धनराशि रु0 352.58 करोड़ की वसूली।

32. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणः-

(1) प्रदेश में 1,80,000 आशा बहुओं को स्मार्टफोन वितरित।

(2) राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रत्येक माह की 15 तारीख को एकीकृत निःक्षय दिवस का आयोजन किया जा रहा है।

(3) राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023 में प्रदेश में 6.25 लाख क्षय रोगियों को नोटीफाई कर देश में इतिहास रचा है।

(4) प्रदेश में कुल 6.25 लाख क्षय रोगी निक्षय पोर्टल पर पंजीकृत। क्षय रोगियों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत 500 रु0 प्रतिमाह की दर से उनके खाते में भुगतान। प्रदेश में कुल 2,56,955 क्षय रोगियों को गोद लिया गया है।

(5) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कुल 1.80 करोड़ परिवार आच्छादित। 28.36 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान की गई। कुल 7.43 करोड़ लाभार्थियों में से 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गुणवत्तायुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर के निकट प्राप्त कराने के उद्देश्य से 21,889 हेल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर संचालित।

(6) प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत 22 सौ एम्बुलेंस सेवा संचालित, माह अक्टूबर 2023 तक कुल 2.71 करोड़ रोगियों को लाभान्वित किया गया है। 250 ए0एल0एस0 एम्बुलेंस सेवा के तहत माह अक्टूबर 2023 तक कुल 5.30 लाख रोगियों को सेवा प्रदान की गयी।

(7) मोबाइल मेडिकल युनिट सेवा के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में माह अक्टूबर 2023 तक कुल 2.11 करोड़ टेली कल्सन्टेशन रोगियों को उपचारित किया गया।

(8) प्रदेश के 75 जनपदों में चिकित्सालयों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। ई-संजीवनी टेली कंसल्टेशन सेवा के अंतर्गत 2.11 करोड़ सेवाएं प्रदान।

(9) प्रदेश के समस्त सी0एच0सी0 पर 15,190 बेड, जिला चिकित्सालय स्तर पर 1,980 बेड एवं मेडिकल कॉलेजों में 2,309 बेडों की वृद्धि की जा रही है।

(10) पहली बार पूरे प्रदेश में 51 जिला चिकित्सालयों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट (एनक्यूएएस) प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में जिला चिकित्सालयों को एनक्यूएएस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(11) यूनिसेफ के सहयोग से आकांक्षात्मक ब्लॉकों में प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है।

(12) विशेष संचारी रोग नियंत्रण/दस्तक अभियान के तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से ए0ई0एस0-जे0ई0 वायरस की रोकथाम हेतु सघन अभियान चलाकर जन जागरूकता। पूर्वांचल क्षेत्र के दिमागी बुखार के कहर से जनता को मिली मुक्ति। ए0ई0एस0 रोगियों की मृत्यु दर में 96 प्रतिशत व जे0ई0 के रोगियों की मृत्यु दर में 97 प्रतिशत की कमी।

(13) ए0ई0एस0 रोगियों की संख्या में 77 प्रतिशत तथा जे0ई0 रोगियों की संख्या में 84 प्रतिशत की कमी।

(14) 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित।

(15) मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 50 शैय्या एकीकृत, 05 आयुष चिकित्सालयों, 05 ई-लाईब्रेरी, 02 महिला छात्रावास एवं 192 आयुष्मान आरोग्य मंदिर एवं 34 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों सहित कुल 238 परियोजनाओं को लोकार्पण किया गया है। प्रदेश में 216 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 154 होम्योपैथिक, 25 यूनानी कुल 395 चिकित्सालयों के नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन। प्रदेश में 1034 आयुषमान आरोग्य मंदिर (पूर्ववर्ती आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर) शत प्रतिशत क्रियाशील।

(16) अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वाराणसी में नेचुरोपैथी केन्द्र एवं पंचकर्म हट्स, जौनपुर में 30 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय, मेरठ में 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय का निर्माण कार्य प्रगति पर। गोरखपुर में योग एवं नेचुरोपैथी में उत्कृष्ट शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना।

(17) ''एक जिला एक मेडिकल कालेज'' नीति के अंतर्गत प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज संचालित तथा 22 मेडिकल कालेज निर्माणाधीन।

(18) मिशन निरामयः के अंतर्गत 300 संस्थाओं में नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठयक्रम संचालित।

33. <u>विशेष :- उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में नम्बर एक बना।</u>

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अन्तर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(2) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान।

(3) 96 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(4) वर्ष 2023 में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 22 लाख से अधिक दीप जलाकर पुनः गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।

(5) कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।

(6) गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान।

(7) ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(8) कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य।

(9) ई-मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी खरीददारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। क्रेता-विक्रेता गौरव सम्मान समारोह-2023 के विभिन्न कटेगरी के एवाड्र्स में प्रदेश को 06 कटेगरी में प्रथम स्थान तथा 02 कटेगरी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।

(10) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

(11) 06 एक्सप्रेस-वे एवं 04 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील, 01 निर्माणाधीन, उत्तर प्रदेश सड़क व एयर कनेक्टिविटी में हुआ सर्वश्रेष्ठ।

(12) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1.83 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश प्रथम।

(13) वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 36.51 करोड़ पौधों का रिकॉर्ड रोपण।

(14) वित्तीय वर्ष 2023-24 में मत्स्य विभाग उ0प्र0 को भारत सरकार द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ अर्न्तस्थलीय मात्स्यिकी राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया।

(15) देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

(16) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त।

(17) माइन मित्रा पोर्टल पर विकसित समाधानों के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश को डिजिटल इण्डिया एवॉर्ड-2022 (प्लैटिनम एवॉर्ड), 25वॉ नेशनल ई-गवर्नेंस एवॉर्ड-2022 (गोल्ड एवॉर्ड) एवं 19वॉ सीएसआईएसआईजी ई-गवर्नेंस एवॉर्ड-2021 प्राप्त हुआ।

(18) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना विकसित करने में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी।

(19) पी0एम0 स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेण्डर को सर्वाधिक ऋण देकर देश में प्रथम।

(20) एनपीएस ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर।

(21) ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट।

(22) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।

.....